

खबर संक्षेप

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इसकी प्रगति की समीक्षा की। इसे और मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की। यह स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर, आसान और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पतंग को पाइप से उतारने में दादा की मौत खर्चा। कोतवाली क्षेत्र के बुर्ज उस्मान मोहल्ले में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 12 वर्षीय पोते को बिजली के कंटे से बचाने के प्रयास में दादा की जान चली गई। कंटे की चपेट में आए पोते की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीडियो सामने आया है।

51 साल के एक्टर संजीब का निधन
नई दिल्ली। टीवी इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है। खबर है कि टीवी के पॉपुलर सीरियल ‘डॉ. आरंभी’ में नजर आ रहे एक्टर संजीब सिंह की अचानक मौत हो गई है। शूटिंग करने के बाद घर लौट रहे एक्टर संजीब सिंह के निधन की घटना ने इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दी है। वे घर लौट रहे थे तभी हार्ट अटैक आया था।

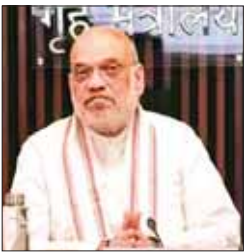
गृहमंत्री ने पड़ोसी मुल्कों से लगते जिलों के एसपी के साथ अहम सम्मेलन को किया संबोधित भारत को घुसपैट मुक्त बनाएंगे, 3 साल में नारकोटिक्स की समस्या भी हो जाएगी हल

एजेंसी ►► नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन समेत तमाम पड़ोसी मुल्कों से लगते जिलों के एसपी के साथ एक अहम सम्मेलन को संबोधित किया। सीमांत जिला पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन-2026 नाम की इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा मजबूत सुरक्षा तंत्र बना रहे हैं। जिससे देश को घुसपैठिया मुक्त करने के साथ ही घुसपैठ ही नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश को जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट में आतंकवाद और नक्सलवाद से निजात मिली है। घुसपैठ को रोकने के साथ ही आने वाले 3 सालों में सरकार नारकोटिक्स की समस्या पर भी विजय प्राप्त करेगी। सम्मेलन में बॉर्डर से लगते 119 जिलों के एसपी और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इनके साथ गृहमंत्री शाह ने कई सुरक्षात्मक मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उनके परामर्श को भी ध्यान से सुना और समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तार से बात भी की।

गृहमंत्री शाह ने 3 बड़े ऐलान किए

119 जिलों के एसपी और अन्य अधिकारी बैठक में रहे शामिल



केंद्र सरकार मजबूत चतुष्कोणीय सुरक्षा गिड बना रही

शाह ने कहा कि मोदी सरकार, संबद्ध सीमा रक्षक बल, राज्य और जिला प्रशासन, भारत सरकार के संबंधित हितधारक तथा स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर एक मजबूत चतुष्कोणीय सुरक्षा गिड का निर्माण कर रही है। बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर में 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

घुसपैठ से जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव
गृह मंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन का मूल कारण घुसपैठ है। मोदी सरकार आइसोलेटेड सीमा चौकी की व्यवस्था से एकीकृत सुरक्षा गिड का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सीमांत क्षेत्रों में जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव की सूचना मिली है।

ग्यांमार बॉर्डर पर 610 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़बंदी हो रही

गृहमंत्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार 31 हजार करोड़ से 1610 किलोमीटर लंबे ग्यांमार बॉर्डर पर बाड़बंदी कर रही है। प्रॉक्सी वार, घुसपैठ, कट्टरपंथ का प्रसार, नारकोटिक्स, तस्करी, ड्रोन, साइबर अपराध, संगठित अपराध और जनसांख्यिकीय परिवर्तन रोकना, सीमा को रहने लायक बनाना और वहां से पलायन रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तटीय सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में भी हम समग्रता से आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट बॉर्डर की कल्पना पर आधारित भारत की बॉर्डर सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में विश्व में सबसे आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था होगी।

रेलवे सुरक्षा और पटरियों की तोड़फोड़ को रोकने व्यापक योजना बना रहे



केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने रेलवे सुरक्षा और पटरियों की तोड़फोड़ को रोकने के लिए कई सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक व्यापक योजना बनाने की बात कही है। इस योजना में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), सीबीआई (सीबीआई) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

(एनआईए) जैसी एजेंसियां शामिल हैं रेलवे सुरक्षा और समन्वय योजनागृह मंत्रालय और रेल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए संयुक्त रणनीति रेल पटरियों पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ या साजिश को नाकाम करने के उपाय। खुफिया एजेंसियों और रेलवे पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने शाह से गुहार लगाई घुसपैठियों को बना रहे स्थायी मूल निवासी कर्नाटक सीएम



एजेंसी ►► नई दिल्ली

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि वे कर्नाटक स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी), 2026 के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। उन्होंने संवैधानिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर कारण बताए। सीएम डीके शिवकुमार ने नागरिकों को चुनाव आयोग की मतदाता सूची के “विशेष गहन संशोधन” भाग लेने में मदद करने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने से रोकना है।

संविधान के प्रावधान का हवाला दिया

शोभा ने कहा कि संविधान पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था करता है। कर्नाटक सरकार द्वारा ‘स्थायी निवास प्रमाण पत्र’ शुरू करना इस संवैधानिक ढांचे के विपरीत है, क्योंकि यह बिना किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के ‘स्थायी निवासियों’ की एक अलग श्रेणी बनाने का प्रयास करता है।

इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह का वर्गीकरण मनमाना है। इसका किसी वैध संवैधानिक उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ‘स्थायी निवासियों’ के रूप में नामित व्यक्तियों का एक अलग वर्ग बनाकर राज्य सरकार वास्तव में ऐसी विशिष्ट कानूनी मान्यता दे रही है, जिसे संविधान के तहत कोई मंजूरी नहीं मिली है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताई

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से यह अधिसूचना और भी चिंताजनक है। इसमें पात्रता के मानदंड मुख्य रूप से निवास और राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थानीय सत्यापन पर आधारित बताए गए हैं। हालांकि, सक्षम केंद्रीय अधिकारियों के माध्यम से भारतीय नागरिकता के सत्यापन को अनिवार्य करने या अवैध प्रवासियों और विदेशी नागरिकों को बाहर करने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं की गई है।
अवैध प्रवासियों को मिलेगा फायदा : उन्होंने कहा कि नतीजा, जो लोग अवैध रूप से भारत में आए हैं या राज्य में गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, वे स्थानीय दस्तावेज दिखाकर या धोखाधड़ी के जरिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। इससे गैरकानूनी रूप से रह रहे लोगों को कानूनी पहचान मिलने का खतरा पैदा हो सकता है।



हिमाचल में 17 आईएस 22 एचएस इधर-उधर

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर 17 आईएस और 22 एचएस अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव कमलेश पंत ने आदेश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऑकार चंद अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे।

ऊंचाई से डरने वाली अमायरा 4वीं मंजिल से कैसे कूद गई?

एजेंसी ►► जयपुर

यहां के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की मौत के मामले में नए सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पिछले साल 1 नवंबर 2025 को स्कूल की चौथी

मंजिल से गिरने से अमायरा की मौत हो गई थी। अब बच्चों के माता-पिता का आरोप है कि जिस बेटी को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, वह अचानक चौथी मंजिल से कैसे कूद सकती है? घटना से पहले अमायरा लगातार मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मां

शिवानी ने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन एक छात्र ने पूरी 55 मिनट तक उनकी बेटी को परेशान किया। वह छात्र अमायरा के आगे बैठा था। अमायरा उसे बार-बार बोर्ड की तरफ देखने के लिए कह रही थी। क्योंकि वह पढ़ाई में फोकस थी और क्लास में ध्यान से बैठी रहती थी।

स्वच्छता नियमों का पालन अब सबकी जिम्मेदारी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

1 अप्रैल 2026 से लागू

अब घर से ही कचरे का पृथक्करण अनिवार्य

- गीला, सूखा, सैनिटरी, स्पेशल-केयर चार अलग श्रेणियों में कचरा दें, ताकि सही निपटान हो सके।

राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से पूरी व्यवस्था पारदर्शी

- रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग और पब्लिक डैशबोर्ड से अब हर शहर की स्वच्छता प्रगति सबके सामने।

नियम तोड़ने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्रवाई

- थोक कचरा उत्पादकों (BWG) के लिए नई व्यवस्था।
- ऑन-साइट प्रोसेसिंग करें या अधिकृत व्यवस्था के तहत जिम्मेदारी निभाएं।
- कचरा अलग होगा, तो शहर बेहतर होगा।
- स्वच्छता में सहयोग करें, नए नियमों का पालन करें।

स्वच्छ शहर-स्वस्थ नागरिक-सुरक्षित भविष्य

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2026

D-11053/26

1996 श्रीनगर हिंसा केस में बड़ा एक्शन

एनआईए की जांच में सामने आया कि हुरियत नेताओं ने भारत विरोधी, पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी नारे लगाए। उन्होंने भड़काऊ भाषणा देकर सशस्त्र संघर्ष की वकालत की

खबर संक्षेप

नीरव शाह अमेरिकी सीनेट चुनाव लड़ेंगे
वॉशिंगटन। भारतीय मूल के महामारी विशेषज्ञ नीरव डी. शाह ने अमेरिकी सीनेट का चुनाव लड़ने का एलान किया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ग्राहम प्लैटनर ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली जिसके बाद नीरव ने यह घोषणा की। विस्कॉन्सिन में भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर जन्मे नीरव शाह कोविड-19 महामारी के दौरान मेन के रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक रहे थे। इसके अलावा, वह मेन के गवर्नर पद के लिए हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव के अंतिम चरण में दूसरे स्थान पर रहे थे।

स्पेन के जंगल में लगी आग, 11 लोगों की मौत
मैड्रिड। स्पेन के अधिकांश हिस्सों में तापमान बढ़ने के बीच जंगल में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जंगल में लगी आग के कई पीड़ितों के शव जले हुए वाहनों के अंदर मिले। आग पर काबू पाने के अभियान में 150 दमकालकर्मी और स्पेन की सैन्य आपातकालीन इकाई के 220 जवान जुटे हुए हैं। यह आग सिएरा दे लांस फिलाब्रेस पहाड़ियों के पास एक छोटे से गांव में लगी। आग लगने के कारण की पुष्टि नहीं की लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि आग बिजली के जमीन पर गिरे तार से भड़की थी।

रूस में दो एआई रोबोट ने किया विवाह
मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को में दो ह्यूमनॉइड रोबोट ने आपस में प्रतीकात्मक विवाह कर लिया। दो एआई ह्यूमनॉइड रोबोट ('रॉबर्ट और मटिल्डा') को आधिकारिक रूप से जीवनसाथी घोषित किया गया। एक रोबोडॉग ने वेडिंग रिंग पहुंचाई। ह्यूमनॉइड रोबोट रॉबर्ट को ऑफिस कर्मचारी और बर्लॉगिंग के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि मटिल्डा को एक बैलेरिना के रूप में बनाया गया है। दोनों ह्यूमन रोबोट्स एआई की मदद से बात कर सकते हैं। मॉस्को की पुरिश्किन लाइब्रेरी में यह विवाह आयोजित किया गया।

8 माह तक चिकित्सा से जुड़े कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को स्पेस के लिए होंगे रवाना

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को कजाखस्तान स्थित बैकानूर कॉस्मोड्रोम (अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल) से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आठ महीने के मिशन पर रवाना होंगे। मिनियापोलिस में यूक्रेनी और भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर जन्मे मेनन आपातकालीन चिकित्सा के चिकित्सक और अमेरिकी अंतरिक्ष बल में कर्नल हैं।

एनआईए ने शब्बीर शाह समेत 6 हुरियत नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायिल की

एजेंसी ►► श्रीनगर

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अलगाववादी संगठन हुरियत कॉन्फ्रेंस के 6 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायिल की है। यह मामला 1996 में श्रीनगर में भीड़ द्वारा हिंसा और पुलिस पर फायरिंग से जुड़ा है। एनआईए ने शुक्रवार को जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में यह चार्जशीट दायिल की। चार्जशीट में जिन 6 कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के नाम हैं, उनमें शब्बीर अहमद शाह, सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील उर्फ मोहम्मद याकूब वकील, जाफिद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी शामिल हैं। सभी 6 नेताओं पर रणबीर दंड संहिता, 1989 के तहत आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश, दंगा और सरकारी कर्मचारी पर हमले के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 भी लगाई गई है।

सभी पर आपराधिक साजिश और पुलिस पर हमले के आरोप



शब्बीर अहमद शाह जाफिद अहमद मीर शकील अहमद बख्शी

3 नेताओं की मौत

अधिकारियों के मुताबिक, सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन और मोहम्मद याकूब वकील का निधन हो चुका है। इसलिए उनके खिलाफ आरोप खत्म माने जाएंगे। लेकिन चार्जशीट में एनआईए ने सबूतों के साथ बताया है कि ये तीनों भी आपराधिक साजिश और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा थे।

चार दशकों में किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड का यह पहला दौरा पीएम मोदी पहुंचे ऑकलैंड, एयरपोर्ट पर पीएम लक्सन ने किया स्वागत

व्यापार, निवेश और रक्षा क्षेत्रों में हुए संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे

एजेंसी ►► नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी चरण के लिए शुक्रवार को ऑकलैंड पहुंचे। पीएम मोदी के यहां पहुंचने पर न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त मुआनपुई सैय्याही समेत कई अधिकारी मौजूद थे। पीएम मोदी ने 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पीएम लक्सन का आभारी हूं। पीएम मोदी ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि चार दशकों में किसी पीएम का न्यूजीलैंड का यह पहला दौरा है। मैं पीएम लक्सन के साथ बातचीत करने और भारत-न्यूजीलैंड दोस्ती के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। बता दें, दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा और अन्य अहम क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। पिछले दो वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया।



पीएम मोदी का स्वागत करते न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन

आर्थिक और व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे

पीएम मोदी ने कहा कि मेरी यह यात्रा मार्च 2025 में पीएम लक्सन की भारत यात्रा के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूती को और आगे बढ़ाएगी। इस यात्रा के दौरान, मैं पीएम लक्सन के साथ आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करूंगा। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर के साथ ही भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है।

भारत आर्थिक महाशक्ति: ट्वायफोर्ड

न्यूजीलैंड के सांसद फिल ट्वायफोर्ड ने कहा कि भारत एशिया में एक राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरा है और न्यूजीलैंड को भारत के साथ गहरी साझेदारी से फायदा होगा। अब हम एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय माहौल में रहते हैं। अब सिर्फ एक सुपरपावर नहीं है, कई हैं। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता इस मामले में बहुत सही समय पर हुआ है।

दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी: नैपले



आर्थिक साझेदारी को गहरा करने के लिए एक मजबूत मंच देता है। इस समझौते के बाद भारत के साझेदार के रूप में न्यूजीलैंड अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करेगा। खेती, इन्वोशेल और एबी-टेक्नोलॉजी में न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता भारत के विकास में, खासकर खेती की उत्पादकता और ग्रामीण आय बढ़ाने में, अहम योगदान दे सकती है।

12 दिसंबर को चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का पहला मैच



शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीजी ने घोषणा की कि 2026-27 बिग बैश लीग सीजन भारत में शुरू होगा। चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम दिसंबर में शुरूआती मैच की मेजबानी करेगा। यह घोषणा पीएम मोदी के साथ एक संयुक्त बयान में की गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बाद में पुष्टि की कि मैलबर्न रेनेगेड्स 12 दिसंबर को ऐतिहासिक सीजन के पहले मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स का सामना करेगा। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर खेला जाने वाला पहला बिग बैश लीग मैच होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। देश 2036 ओलंपिक के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है।

स्टीव वॉ और लीसा से मिले पीएम



एमसीजी दौरे के दौरान पीएम ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ को लगभग दो दशक पुरानी एक तस्वीर भेंट की। यह तस्वीर उस समय की थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी स्टीव वॉ से मुलाकात हुई थी। पूर्व महिला कप्तान लीसा स्थालेकर के आग्रह पर पीएम मोदी ने बैट पर अपने हस्ताक्षर दिए।

नारी स्वास्थ्य समस्याओं में भरोसेमंद

कमर-पेड़ में दर्द, खून की कमी, कमजोरी, हथेली-तलवों में जलन, हार्मोन्स असंतुलन चिड़चिड़ापन आदि कठिन समस्याओं में सहायक

हेमपुष्पा

90 वर्षों से No.1 पुमन हेल्थ टॉनिक

Helpline: 011-23261111, rajvaidyacare@gmail.com

हिंसा फैलाने पहले से रची थी साजिश
एनआईए की जांच में सामने आया कि हुरियत नेताओं ने भारत विरोधी, पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी नारे लगाए। उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर सशस्त्र संघर्ष की वकालत की। एनआईए ने कहा कि बारीक जांच से साफ हुआ कि यह हिंसा पहले से रची गई बड़ी साजिश का हिस्सा थी। हुरियत नेतृत्व ने अंतिम यात्रा को अलगाववादी सोच फैलाने, भारत सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने, अशांति फैलाने और पुलिस पर हमला करवाने के लिए मंच बनाया था।

देश की मिट्टी में मरने की चाहत दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी पूर्व पीएम शेख हसीना, कोर्ट में करेंगी 'सरेंडर'



पूर्व पीएम शेख हसीना

एजेंसी ►► नई दिल्ली

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा है कि वह दिसंबर में भारत से बांग्लादेश देश लौटेंगी और कोर्ट में सरेंडर करेंगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ अवामी लीग के कई सीनियर नेता भी बांग्लादेश लौटकर आत्मसमर्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लगभग सभी बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कई लोग छिपकर रहने को मजबूर हैं। बता दें, हसीना 2024 में सरकार विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद उन्हें छात्र आंदोलन पर कार्रवाई से जुड़े मामले में मौत की सजा सुनाई गई। वह इन आरोपों से इनकार करती रही हैं।

सरकार से वापसी पर कोई बातचीत नहीं
शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश लौटने को लेकर सरकार से कोई बातचीत नहीं की है। उनका कहना है कि लोकतंत्र, चुनाव, अवामी लीग के राजनीतिक अधिकार और न्याय जैसे मुद्दों पर पदों के पीछे बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस भेजने के लिए भारत को लगातार पत्र लिख रही है। मुझे वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही लौटूंगी। हालांकि, हसीना के इस दावे पर बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं भारत ने भी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की। इससे पहले अप्रैल में भारत ने कहा था कि वह बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विचार कर रहा है और नई सरकार के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।

गलती की है तो फैसला जनाते करेंगे
शेख हसीना ने कहा कि उन्हें जेल जाने का डर नहीं है, क्योंकि वह पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में लंबे समय तक रहने वाली किसी भी सरकार से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसका फैसला अदालत नहीं, जनता को करना चाहिए। अगर हमारी सरकार से गलतियां हुई हैं, तो जनता फैसला करेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में 2024 के छात्र आंदोलन पर कार्रवाई में करीब 1,400 लोगों की मौत होने की बात कही गई है। इसी मामले में शेख हसीना को अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी। हसीना ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अदालत की सुनवाई शुरू होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी।

यूएन में संघर्ष संबंधी यौन हिंसा की निंदा भारत बोला- यह एक जघन्य कृत्य राजनीतिक दमन का बड़ा हथियार

एजेंसी ►► वॉशिंगटन

भारत ने संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा (सीआरएसवी) की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा पर खुली बहस में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पी. हरीश ने कहा कि इस तरह की हिंसा दण्ड मुक्ति की प्रचलित संस्कृति के बीच



जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में सत्यापित मामलों में हुई तीव्र वृद्धि सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा में भारत के महत्वपूर्ण योगदानों पर प्रकाश डाला।

ओमान पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर रक्षा, व्यापार, साइबर, समुद्री सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा

एजेंसी ►► मस्कट

विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंचे। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। जयशंकर ने ओमान की राजधानी मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसादी से मिले। उन्होंने एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा कि हमारे सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके खुशी हुई। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश,



जयशंकर और बद्र अलबुसादी

कर्नेक्टिविटी, समुद्री मामलों, टेक्नोलॉजी, रक्षा और साइबर व एआई के क्षेत्रों पर केंद्रित रही। खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों और शांति व स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों पर विस्तार से विचारों का आदान-प्रदान हुआ। हमारी बातचीत हमारी रणनीतिक साझेदारी के भरोसे और मजबूती को दर्शाती है।

नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ समझौता हो या न हो, तेहरान के पास नहीं होंगे परमाणु हथियार

एजेंसी ►► तेल अवीव/वॉशिंगटन

अमेरिकी और ईरान के बीच युद्धविराम के टूटने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और इजराइल हर स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि देश की हवाई श्रेष्ठता बनाए रखना उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का आधार है। उन्होंने कहा कि हमारी नीति साफ है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, चाहे कोई समझौता हो या न हो। अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान परमाणु हथियार हासिल कर चुका होता। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और हमारे सामने नई चुनौतियां उभर रही हैं।



ईरानी विदेश मंत्री ने भी की बातचीत

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद अल बुसैदी और तुर्किए के विदेश मंत्री हकन फिदैन के साथ फोन पर बातचीत की।

चीन के सबसे बड़े बांध पर भूवैज्ञानिकों की चेतावनी ब्रह्मपुत्र पर बांध से आ सकती है तबाही, भूस्खलन और भूकंप का खतरा

एजेंसी ►► बीजिंग

चीन तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना बनाने में जुटा है। वहीं, चीनी भूवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह विशाल बांध एक सक्रिय फॉल्ट लाइन के ऊपर स्थित है और इससे भूस्खलन और भूकंप का खतरा उत्पन्न हो सकता है। चीन की सरकारी पत्रिका 'सेडिमेंट्री जियोलॉजी एंड टेथियन जियोलॉजी' में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार, पैग्ज़ेन फॉल्ट सीधे उस क्षेत्र से होकर गुजरता है जहां जलविद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। 'चेंगदू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह फॉल्ट लाइन बांध, सड़कों और पुलों जैसी बुनियादी संरचनाओं की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है।

यह विशाल बांध एक सक्रिय फॉल्ट लाइन के ऊपर स्थित

रिसर्च के अनुसार, इस क्षेत्र की चट्टानें अत्यधिक कमजोर हैं और यहां की ढीली मिट्टी के कारण बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड की आशंका बनी रहती है। यह बांध श्री गोरजेस बांध की तुलना में तीन गुना अधिक बिजली उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी नींव की भार वहन क्षमता फॉल्ट गतिविधि के कारण असुरक्षित है। इससे



तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन बना रहा बांध

कभी भी तबाही मच सकती है। यह फॉल्ट लाइन बांध हिमालय की उन सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित है जहां भारतीय और यूरेशियन प्लेटों का टकराव होता रहता है, जिससे भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। चीनी वैज्ञानिकों ने 2017 में मिलिन में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप का हवाला देते हुए इसे वास्तविक आपदा जोखिम बताया है।

भारत पर होगा असर
बता दें, यारलुंग त्सांगपो नदी भारत में प्रवेश करने के बाद सियांग और आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के इतने बड़े बांध से नदी के प्राकृतिक जल प्रवाह में बदलाव आ सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में कृषि, पर्यावरण और जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। वहीं, अवाजक पानी छोड़े जाने की स्थिति में विनाशकारी बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है।
राजनीतिक तनाव
चीन की विशाल बांध परियोजना पहले ही भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र बन चुकी है। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की गतिविधियों को लेकर बार-बार चिंता व्यक्त की है, जिसमें जल सुरक्षा, पारिस्थितिकी और निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए संभावित खतरों का हवाला दिया गया है।

पुलिस मुख्यालय ने बड़े पैमाने पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की

मप्र पुलिस में पदोन्नति का रास्ता साफ: एक साथ 400 निरीक्षक बनेंगे उप पुलिस अधीक्षक, आरक्षक तक मिलेगा प्रमोशन का लाभ

हरिभूमि न्यूज़ ►► भोपाल

मप्र में करीब एक दशक से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पदोन्नति पर लगी रोक हटने के बाद पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने बड़े पैमाने पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत एक साथ करीब 400 निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) बनाया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। विभागीय स्तर पर माना जा रहा है कि गृह विभाग की मंजूरी के बाद जल्द ही विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होगी और इसके बाद पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे।

समय तक रोक रहने के कारण नियमित डीएसपी के लगभग 113 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने और कार्यवाहक अधिकारियों को नियमित पद देने के उद्देश्य से करीब 410 निरीक्षकों को डीएसपी बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इनमें कार्यवाहक डीएसपी के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी भी शामिल हैं।

पुलिस कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश

पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाइयों को पत्र जारी कर पदोन्नति नियम-2025 के तहत पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें उपनिरीक्षक से निरीक्षक, निरीक्षक से डीएसपी, रक्षित निरीक्षक से निरीक्षक तथा अन्य संबंधित पदों की पात्रता सूची और अभिलेख मांगे गए हैं। सभी जिलों और इकाइयों से रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद अंतिम प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जाएगा।

एसआई को निरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक को एसआई बनाया जाएगा

पदोन्नति की प्रक्रिया केवल डीएसपी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका लाभ पुलिस विभाग की पूरी श्रृंखला को मिलेगा। सबसे पहले निरीक्षकों को डीएसपी पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इसके बाद खाली होने वाले निरीक्षक पदों पर रक्षित निरीक्षकों को पदोन्नति मिलेगी। फिर उपनिरीक्षक (एसआई) को निरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को एसआई बनाया जाएगा। यह प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए आरक्षक स्तर तक पहुंचेगी, जिससे हजारों पुलिसकर्मियों के पदोन्नति के अवसर खुलेंगे। उनको इसका लाभ मिलेगा।

प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजने की तैयारी

परिवहन विभाग में भी लंबे समय बाद पदोन्नति शुरू

उधर, परिवहन विभाग में भी लंबे समय बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई है। विभाग के 27 परिवहन उपनिरीक्षकों को परिवहन निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। हालांकि ये पदोन्नतियाँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों और भविष्य में आने वाले न्यायालय के आदेशों के अधीन रहेंगी। पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से पुलिस विभाग में लंबे समय से रुका करियर गोंथ का रास्ता खुलने की उम्मीद है। इससे न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव होगा।

अपना दल (एस) ने पेश किया 100 दिन का रोडमैप

भोपाल। अपना दल (एस) मप्र ने संगठन विस्तार एवं सदस्यता अभियान को गति देने एक वचुंअल बैठक का आयोजन किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव एवं मप्र प्रदेश प्रभारी आर बी सिंह पटेल रहे, जहां रणनीतिकार डॉ अ तुल ने मलिकराम

एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आगामी 100 दिनों का रोडमैप साझा किया। बैठक के दौरान आगामी 19 जुलाई को भोपाल में एक विशेष बैठक की घोषणा भी की गई, जिसमें सभी जिलाध्यक्षों को अपने अब तक के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इस वचुंअल कार्यक्रम में प्रदेशभर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान वरिष्ठ नेता देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी संगठन विस्तार को लेकर अपने मूल मंत्र साझा किए। कार्यक्रम में प्रदेश भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें राजेश्वर मिश्रा, एस आर नागले, मोहित गुप्ता, कैलाश गांवडे, सीता सरण सिंह, डीपी पटेल, आर के सनोडिया, रौशन पटेल और फिल्म अभिनेता गौरव प्रतीक आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस बैठक में सिंगरौली जिला अध्यक्ष जिलोकी सिंह, इंदौर जिला अध्यक्ष टीकम चंद शर्मा, मैहर जिला अध्यक्ष मनोज पटेल, भोपाल जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नाहर, ग्वालियर जिला अध्यक्ष राहुल सिंह, बैतुल जिला अध्यक्ष डॉ. अनूप चौरे और छतरपुर जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल उपस्थित रहे।

टोना-टोटका करने वाली महिला कहकर किया बदनाम बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में देवरानी, उसकी पुत्री और पुत्र गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज़ ►► कोरबा

उरगा थाना क्षेत्र के भांटापारा कुदुरमाल में प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को 2 साल से मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने देवरानी, उसकी पुत्री और पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मामले में बीएनएस और टोनाही प्रताड़ना अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

थाना उरगा में अपराध क्रमोंक 304/2026 के तहत सत्यभामा वैष्णव पति स्व. ओमप्रकाश वैष्णव उम्र 65 वर्ष निवासी कुदुरमाल वार्ड क्र. 04 ने शिकायत दर्ज कराई।



पीड़िता ने बताया कि उनकी देवरानी लक्ष्मीन वैष्णव उर्फ लक्ष्मी, उसकी पुत्री चंचल वैष्णव और पुत्र किशन वैष्णव उर्फ गोतू पिछले कई वर्षों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी रोज घर के सामने आकर गाली-गलौज करते हैं। बुजुर्गों को जादू-टोना करने का आरोप लगाकर टोना-टोटका करने वाली महिला कहकर पूरे मोहल्ले में बदनाम करते हैं।

मप्र पुलिस में पदोन्नति का रास्ता साफ: एक साथ 400 निरीक्षक बनेंगे उप पुलिस अधीक्षक, आरक्षक तक मिलेगा प्रमोशन का लाभ

प्रदेश में वर्तमान में 297 कार्यवाहक डीएसपी पदस्थ

जानकारी के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 297 कार्यवाहक डीएसपी पदस्थ हैं। पदोन्नति पर लंबे समय तक रोक रहने के कारण नियमित डीएसपी के लगभग 113 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने और कार्यवाहक अधिकारियों को नियमित पद देने के उद्देश्य से करीब 410 निरीक्षकों को डीएसपी बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इनमें कार्यवाहक डीएसपी के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी भी शामिल हैं।



कालापीपल को दी 30.86 करोड़ की सौगात, दोहराया यूसीसी लागू करने का संकल्प

फिल्मी गाने की तरह शाजापुर हमारे लिए सोना उगलने वाली धरती: मुख्यमंत्री

किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन एवं ‘हरा-भरा कालापीपल’ पौधरोपण अभियान प्रारंभ



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कालापीपल अद्भुत क्षेत्र है। मां राज-राजेश्वरी की इस पर असीम कृपा है। आज यह क्षेत्र पौधरोपण में नया रिकॉर्ड बना रहा है। नेवज, लकुंदर, चिल्लर, पार्वती इन पांच नदियों की क्षेत्र को कृपा मिल रही है। परमात्मा ने शाजापुर को अद्भुत सौंदर्य दिया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में शाजापुर जैसा जिला है। उन्होंने कहा कि एक गाना है, ‘मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती, मेरे देश की धरती...’ इसी गाने की तरह शाजापुर हमारे लिए सोना उगलने वाली धरती भी है।

डॉ. यादव शाजापुर जिले के कालापीपल को 30.86 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। कई कामों के लोकार्पण और भूमिपूजन किए। उन्होंने आयोजित किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन एवं ‘हरा-भरा कालापीपल’ पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। इससे पहले कालापीपल में उनका ‘रोड शो’ हुआ। कार्यक्रम के दौरान डॉ. यादव ने शाजापुर को नई सड़कें और रेलवे ओवर ब्रिज देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसी महीने राज्य में यूसीसी लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। देश में अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिए।

लोकार्पण का औपचारिकता का कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों का 6-6 महीने के ब्याज का डझाट खत्म हो जाएगा। अब हम एक साल के लिए लोन देंगे। किसानों के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है।

खेत में किसान और सीमा पर जवान का सम्मान

डॉ. यादव ने कहा कि खेत में किसान और सीमा पर जवान, दोनों का सम्मान, ये है भाजपा की पहचान। हमने पारस पथर तो नहीं देखा, लेकिन यह पक्की बात है कि अगर सूखे खेत को पानी मिल जाए, तो सोना उगलने लगता है।

सीएम ने किया उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मप्र के सड़क अधोसंरचना विकास में शुक्रवार 10 जुलाई को एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। आज उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमिपूजन हुआ। लगभग 98.73 किमी लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपए की लागत से मप्र सड़क विकास निगम द्वारा किया गया। यह परियोजना उज्जैन दक्षिण, घड़िया, नागदा-खाचरौद, आलोट एवं जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।

व्यापारिक व कृषि विकास को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक एवं कृषि विकास को नई गति प्रदान करेगी। किसानों को अपनी उपज विभिन्न कृषि उपज मंडियों तक शीघ्र पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, वहीं उद्योगों, लॉजिस्टिक्स एवं निवेश गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा समय एवं ईंधन की बचत होगी।

नर्सिंग छात्रा की उसके कमरे में घुसकर अज्ञात युवक ने की हत्या

हरिभूमि न्यूज़ ►► दुर्ग

वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर में शुक्रवार को एक नर्सिंग छात्रा की उसके पीजी के कमरे में अज्ञात युवक द्वारा घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के समय मृतक को सहेली बाथरूम में नहाने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान एक युवक कमरे में पहुंचा और धारदार हथियार से छात्रा पर हमला कर फरार हो गया। गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को सूचना मिलने पर भिलाई नगर सीएसपी उरगा पुलिस ने बीएनएस की धारा 296, 351(3), 3(5) और 4, 5 टोनाही प्रताड़ना अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

आठ सौ करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को मिल रही गति सरकार का 3,778 करोड़ का मेगा प्लान, उज्जैन समेत सात जिलों के धार्मिक-पर्यटन स्थलों का भी होगा कायाकल्प



नावघाट खेड़ी में 163 करोड़ रुपए की लागत से घाटों का निर्माण

आंकरेश्वर और नावघाट खेड़ी में 163 करोड़ की लागत से घाटों का निर्माण होगा। ममलेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स और आसपास के क्षेत्र के विकास पर 119 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं खरगोन में अहिल्या लोक के निर्माण के लिए 110 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 70 करोड़ से आंकरेश्वर सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें इंदौर, उज्जैन, आंकरेश्वर और महेश्वर में आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी।

आठ सौ करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को मिल रही गति सरकार का 3,778 करोड़ का मेगा प्लान, उज्जैन समेत सात जिलों के धार्मिक-पर्यटन स्थलों का भी होगा कायाकल्प

हरिभूमि न्यूज़ ►► भोपाल

सिंहस्थ-2028 को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने 3,778 करोड़ रुपये की लागत से उज्जैन सहित सात जिलों के धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों के विकास का खाका तैयार किया है। इस योजना के तहत सड़क संपर्क, घाट निर्माण, मंदिर परिसरों का विकास, श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं और पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिलहाल

800 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे हैं, जिन्हें 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य सिंहस्थ के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को केवल महाकाल तक सीमित न रखते हुए आसपास के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक भी आकर्षित करना है। इसके लिए संस्कृति एवं पर्यटन विभाग महाकाल लोक के साथ अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार करेगा।

हाईटेक पीरियोडिक ओवरहालिंग का कार्य किया पूरा रेलवे का सेप्टी मिशन: कोच फैक्ट्री में 280 कोचों के मेंटेनेंस का रिकॉर्ड

हरिभूमि न्यूज़ ►► भोपाल

रेलवे ने यात्री सुरक्षा और आरामदायक सफर की दिशा में अपने ‘सेप्टी मिशन’ को नई गति दी है। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल स्थित ‘सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना (कोच फैक्ट्री)’ ने चालू वित्त वर्ष (2026-27) के प्रथम तिमाही कुल 286 कोचों का सफलतापूर्वक पीरियोडिक ओवरहॉलिंग (पीओएच) कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। जबकि जून में 99 कोचों का पीओएच किया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों की सतत निगरानी में भोपाल कारखाना प्रबंधन ने टीम भावना और सुनियोजित कार्ययोजना के साथ यह सफलता हासिल की। इस हाईटेक मरम्मत से न केवल यात्रियों का सफर सुरक्षित और आरामदायक होगा, बल्कि ट्रेनों के तकनीकी खराबी के कारण निरस्त होने या देरी से चलने की संभावना भी कम हो जाएगी।



हाईटेक परियोडिक ओवरहॉलिंग कार्य को पूरा करते कर्मचारी।

हाईटेक ओवरहॉलिंग: अब सफर में नहीं लगेंगे झटके

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों की सुरक्षा और स्थिरता को विश्वस्तरीय बनाना है। पीरियोडिक ओवरहालिंग के तहत उन कोचों की पूरी तरह से कायाकल्प की जाती है, जो अपनी निर्धारित दूरी या समय सीमा पूरी कर चुके होते हैं।

ऐसे किया जाता है मेंटेनेंस का काम

- कोचों की बॉडी और अंडर गियर की मरम्मत कर परिवालन में अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
- ट्रॉली, बोगी के सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स की मरम्मत की जाती है, जो सुरक्षा को दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- एयर ब्रेक सिस्टम, बफर व अन्य संरचनात्मक उपकरणों की मरम्मत की जाती है, जिससे यात्रियों को झटका-रहित और सुरक्षित यात्रा का अनुभव हो सके।
- व्हील और एक्सल का रखरखाव और मरम्मत कर परिचालन सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाता है।

सांची रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत किया पुनर्विकसित

भोपाल। विश्व धरोहर सांची का रेलवे स्टेशन सहित भोपाल रेल मंडल के चार स्टेशन विश्वस्तरीय सुविधाओं से लेस हो गया। इसी योजना के तहत भोपाल मंडल के सांची, विदिशा, शिवपुरी व

अशोक नगर स्टेशन का काम पूरा होने के साथ ही यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं आने वाले दिनों में मिलने लगेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वचुंअल तरीके से 17 जुलाई को

भोपाल मंडल के चार स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर भोपाल रेल मंडल की ओर बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सांची

रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 15.32 करोड़ की लागत से किया गया है, जिसके तहत स्टेशन को आधुनिक, सुविधायुक्त एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है।

रिकॉर्ड में धान स्टॉक दर्ज था, भौतिक सत्यापन से गायब



महासमुंद में करीब 17.93 करोड़ रुपये का कथित धान घोटेला उजागर

हरिभूमि न्यूज़ ►► महासमुंद

जिले में करीब 17.93 करोड़ रुपये का कथित धान घोटेला सामने आया है। इस मामले ने प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में कई खरीदी केंद्रों के रिकॉर्ड में धान का स्टॉक दर्ज था। हालांकि, भौतिक सत्यापन के दौरान वहां स्टॉक नहीं मिला। वर्ष 2025-26 के धान खरीदी सत्र में 182 खरीदी केंद्रों से 1,01,95,681.20 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मिलिंग के बाद रिकॉर्ड के अनुसार 57,860.47 कुंतल धान शेष होना चाहिए था। लेकिन, जांच के दौरान 54 केंद्रों पर यह स्टॉक नहीं मिला। गायब धान का मूल्य करीब 17 करोड़ 93 लाख 67 हजार 457 रुपये आंका गया है। यह समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति कुंतल के आधार पर है।

15 समितियों के खिलाफ केस दर्ज

जिला विपणन अधिकारी ने करोड़ों रुपये मूल्य का धान स्टॉक में नहीं मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अब तक 15 सहकारी समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की

रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। 54 खरीदी केंद्रों पर धान का स्टॉक नहीं मिलने के बावजूद केवल 15 समितियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। शेष 39 केंद्रों के संबंध में आगे की

यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए: डीसीएम

भोपाल। भोपाल रेलवे स्टेशन पर ऐसे तो नियमानुसार 15 मिनट का समय यात्रियों को लेने और छोड़ने के लिए पर्याप्त माना जाता है, लेकिन जब स्टेशन परिसर में भीड़ और अंटी चालकों की मनमर्जी जारी हो तो यह समय आधा घंटे में कम तब्दील हो जाता है। ऐसी ही कुछ पाकिंग को लेकर भोपाल स्टेशन पर यात्रियों को मंडल मुख्यालय को शिकायतों की जा रही थी। इसके बाद गुरुवार को यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा स्टेशन परिसर में उपलब्ध वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-6 की ओर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या-6 की ओर स्थित वाहन पार्किंग को उपलब्धता, यातायात प्रबंधन, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, संकेतक बोर्ड, प्रकाश व्यवस्था तथा स्वच्छता की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाए। साथ ही आवश्यक सुधारालमक कार्य समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किए जाए।



दो आतंकियों को सुरक्षा कर्मियों ने किया ढेर, तीन को ज़िंदा दबोचा!

मॉकड्रिल: हाईकोर्ट में आतंकी हमला!

जबलपुर। हाईकोर्ट में शुक्रवार शाम अचानक हुए आतंकी हमले ने सबको चौंका दिया। व्हीआईपी गेट से फायरिंग करते हुए घुसे आतंकियों पर जबाबी कार्रवाई की। इस दौरान दो आतंकियों को मार गिरया गया तो वहीं तीन को ज़िंदा दबोचा गया। सूचना पर कई थानों का बल, बीडीडीएस की टीम, फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस के वाहन मौके पर पहुंचे। अचानक सायरन बजते वाहनों और भारी पुलिस बल की चहलकदमी ने अधिवक्ताओं सहित सभी को चौंका दिया, बाद में पता चला कि एहतियात के तौर पर मॉकड्रिल आयोजित की गई थी।

दरअसल शुक्रवार को शाम पौने पांच बजे उच्च न्यायालय जबलपुर की सुरक्षा में पदस्थ अधिकारी-कर्मचरियों के द्वारा आकस्मिक आतंकी हमला एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये मॉक ड्रिल की कार्यवाही एसपी सम्पत उपाध्याय एवं सिद्धार्थ चौधरी सेनानी 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर के मार्ग-दर्शन में सम्पन्न करायी गई। मॉक ड्रिल की कार्यवाही में हाईकोर्ट सुरक्षा की टीम सहित बीडीडीएस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की टीम के द्वारा सयुंक्त रूप से मॉक ड्रिल की कार्यवाही में भाग लिया गया। जिसमें मॉक ड्रिल कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय परिसर की सुरक्षा, न्यायाधिपति महोदयों की सुरक्षा, कोर्ट रूम की सुरक्षा एवं आकस्मिक आगजनी से बचाव की ड्रिल की गई।



दो आतंकियों किया ढेर, तीन पकड़ा

मॉकड्रिल के दौरान हुए आतंकी हमले की कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिरया तो वहीं तीन को ज़िंदा धर दबोचा। इसके बाद बीडीडीएस टीम द्वारा बम विस्फोटक तलाश कर पहचानने एवं उसके नष्टीकरण करने संबंधित मॉक ड्रिल तथा हथूयागत की आपात स्थिति में किसी व्यक्ति की जान बचाने हेतु सीपीआर का प्रदर्शन भी किया। आकस्मिक आतंकी हमला मॉक ड्रिल की रूप रेखाएं अभ्यास एवं प्रदर्शन उच्च न्यायालय सुरक्षा जबलपुर में पदस्थ सउनि अजय परोते के द्वारा किया गया।

न्यायधीशगणों व अधिकारी रहे मौजूद

मॉक ड्रिल प्रदर्शन के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया, सहित समस्त न्यायाधिपति एवंधर्मज्ज सिंह राठौर रजिस्ट्रार जनरल, हर्ष सिंह बहरावत रजिस्ट्रार प्रशासन, पीएल परतेती अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हाईकोर्ट सुरक्षा, पंकज परमार उप पुलिस अधीक्षक हाईकोर्ट सुरक्षा, वैभव कुमार दुबे निरीक्षक, समरेश उपाध्याय निरीक्षक, सक्कन सिंह निरीक्षक, पंकज सिंह निरीक्षक बीडीडीएस, सहित माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा जबलपुर में पदस्थ समस्त अधिकारी-कर्मचारी एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के भी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

ट्रैफिक सिग्नल विवाद में हाईकोर्ट ने कहा

सिग्नलों में एकरूपता के लिए एक ही एजेंसी से संचालन पर विचार करे सरकार

जबलपुर। शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था और बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नलों को लेकर मप्र हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा को डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर के ट्रैफिक सिग्नलों में एकरूपता लाने के लिए इनके संचालन का जिम्मा किसी एक ही एजेंसी को सौंपने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक इस संबंध में अपना प्रस्ताव या राय पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है। नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ. पी.जी. नाजपांडे और नयागांव निवासी रजत भागव ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जबलपुर शहर के लगभग सभी प्रमुख चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, जिससे पूरी यातायात व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इससे पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले को बेहद संजीदगी से लेते हुए राज्य सरकार, जबलपुर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी (ट्रैफिक), जसिम्पट नगर निगम और जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

एमपी स्टेट बार काउंसिल में लगभग तय हुई जीत

जबलपुर ने रचा इतिहास : आरके सिंह सैनी को एक जिले से मिले सर्वाधिक मत

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल चुनाव-2026 की मतगणना में जबलपुर ने नया इतिहास रच दिया। पूर्व वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी को जबलपुर जिले से अब तक किसी भी एक प्रत्याशी को मिले सबसे अधिक 980 मत प्राप्त हुए हैं। इसे प्रदेश के अधिवक्ता चुनावों में एक नया रिकार्ड माना जा रहा है। सैनी को अब तक मिले कुल मतों की संख्या 1387 हो गई है। जबलपुर से सैनी के अलावा आशीष त्रिवेदी व मनीष तिवारी भी बढ़त बनाए हुए हैं।

अब तक 34,920 मतों की गणना 27 हजार की गिनती शेष

मुख्य निर्वाचन अधिकारी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति एसके पालो व वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ के अनुसार शुक्रवार को जबलपुर की मतपेटियों की गिनती पूरी हो चुकी है। बहुत हासिल करने वालों में राकेश सिंह भदौरिया, आरके सिंह सैनी, विवेक सिंह, नरेंद्र कुमार जैन और हितेन्द्र जय हाडिया शामिल हैं। अब तक 34,920 मतों की गणना पूरी हो चुकी है, जिनमें 33,654 मत वैध पाए गए हैं, जबकि 1,266 मत निरस्त हुए। लगभग 27



हजार मतों की गिनती अभी शेष है।

जबलपुर के अधिवक्ता समुदाय में उत्साह का माहौल

आरके सिंह सैनी की ऐतिहासिक बढ़त से जबलपुर के अधिवक्ता समुदाय में उत्साह का माहौल है। शुक्रवार को समर्थकों ने हाईकोर्ट परिसर में सैनी को लेकर जुलूस निकाला। समर्थकों का कहना है कि एक ही जिले से किसी प्रत्याशी को इतनी बड़ी संख्या में मत मिलना पहली बार हुआ है। जिसने संस्कारधानी को प्रदेशभर में नई पहचान दिलाई है।

अधिवक्ता हितों के लिए हमेशा साथ खड़ा रहूंगा

जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता साथियों ने जो स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। मैं हमेशा अधिवक्ता समाज के हितों के लिए उनके साथ खड़ा रहूंगा।

-आरके सिंह सैनी, पूर्व वाइस चेयरमैन, स्टेट बार

साढ़े पांच किलो गांजा तस्करी पर दो साल की जेल

जबलपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश प्रवेन्द्र सिंह ने गांजा तस्करी के आरोप में जबलपुर निवासी सचिन सोनी को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास मुगलता होगा। अभियोजन के अनुसार तीन मार्च, 2025 को संजीवनी नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से करीब साढ़े पांच किलो गांजा बरामद किया था। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से एजीपी अरविंद जैन ने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामला पहुंचा मुख्यमंत्री के दरबार

लोकायुक्त ट्रैप के बाद भी नहीं मिली अभियोजन की स्वीकृति

हरिभूमि, जबलपुर।

कटनी के बहुचर्चित रिश्तत प्रकरण ने अब प्रदेश की भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वर्ष 2022 में लोकायुक्त द्वारा 60 हजार रुपये की कथित रिश्तत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक संजय सिंह के खिलाफ चार साल बाद भी अभियोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने का मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है।

मध्य भारत मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम जापन सौंपते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। संगठन का आरोप है कि रंगे हाथों पकड़े जाने और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई में हुई असामान्य देरी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

चार साल... आखिर किसके संरक्षण में अटकी रही फाइल ?

ज्ञापन का सबसे बड़ा सवाल यही है। यदि लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, जांच आगे बढ़ी थी, तो फिर अभियोजन स्वीकृति में चार वर्ष क्यों लग गए? क्या फाइल किसी अधिकारी की टेबल पर धूल खाती रही? क्या जांबजूझकर निर्णय टाला गया? या फिर भ्रष्टाचार के मामलों में भी प्रभावशाली अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था काम करती है? इन सवालों का जवाब अब शासन से मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री से मांगी उच्चस्तरीय जांच मोर्चा ने मांग की है कि— चार वर्षों की देरी की जांच हो। फाइल रोकने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। नागरिक आपूर्ति निगम में समर्थन मूल्य खरीदी की स्वतंत्र जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति के लिए समय-सीमा तय की जाए।

मध्य भारत मोर्चा का हमला—‘जिरो टॉलरेंस’ सिर्फ भाषणों में, फाइलों में क्यों दफन हो जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले?

नगर निगम की डेयरी दुकानों पर कार्रवाई, दूध-पनीर के लिए सैंपल दो संचालकों पर 4 हजार का जुर्माना

जबलपुर। नागरिकों के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम ने डेयरी दुकानों पर औचक जांच अभियान चलाया। नगर निगम मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गोयल के नेतृत्व में निगम एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने संभाग क्रमांक-3 एवं 4 के अंतर्गत आने वाली डेयरी दुकानों का निरीक्षण किया।

कार्रवाई के दौरान नरेंद्र डेयरी, मंदर डेयरी, पूजा डेयरी और न्यू पूजा डेयरी से दूध एवं पनीर के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों की जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले दो डेयरी संचालकों पर मौके पर ही 4 हजार रुपये का स्पॉट फाइन लगाया। नगर निगम मजिस्ट्रेट अरुण कुमार



गोयल के साथ स्वास्थ्य अधिकारी अभिनव मिश्रा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी, धर्मेन्द्र राज, अर्जुन यादव, पोलाराव, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एवं स्वच्छता निरीक्षक कार्रवाई में शामिल रहे। अभियान के दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलिथीन

का उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जल संरक्षण की दिशा में नगर निगम का बड़ा अभियान, शहर में बनेंगे 1500 सोकपिट

जबलपुर। जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम ने शहर में बड़ा अभियान शुरू किया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नु की पहल पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा जल संचय के लिए 1500 स्थानों पर सोकपिट बनाए जाएंगे। इसके तहत सभी शासकीय हैंडपंपों और बोरवेल के पास रिचार्ज सोकपिट तैयार किए जा रहे हैं, ताकि बारिश का पानी जमीन के भीतर पहुंचकर भूजल स्तर को बढ़ा सके। महापौर ने बताया कि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में शहर के 100 से अधिक पारंपरिक कुओं की सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य भी कराया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ मनमोहन नगर पार्क में किया गया, जहां 60 फीट गहरे और 6 इंची बोर के चारों ओर 3×3×3 आकार का सोकपिट तैयार कर बाटर हवॉरिंटज सिस्टम शुरू किया गया। इस सिस्टम से आसपास के दो शासकीय बोरिंग को भी रिचार्ज



किया जाएगा। महापौर ने कहा कि उद्देश्य केवल पानी बचाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्रोतों को सुरक्षित करना है। इस अवसर पर निगमाध्यक्ष रिकुंज विज, एमआईसी सदस्य विवेकमय सोनकर, डॉ. सुभाष तिवारी, पार्षद श्रीमती रेणु कोरी, प्रीतम सिंह सेंगर, वर्षा मेहता, नीरज, संदीप जायसवाल, मनीष तड़से

सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

वहीं, अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान ने भोंगाद्वार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने रॉ-वाटर पंपिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन प्रक्रिया का निरीक्षण किया तथा जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला की व्यवस्थाएं देखीं। अपर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए

चार साल से कौन बचा रहा रिश्ततखोर अफसर?



अब नजर मोपाल पर

मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप जाने के बाद अब निगाहें मोपाल पर टिक गई हैं। यदि शासन इस मामले में उच्चस्तरीय जांच के आदेश देता है, तो केवल रिश्तत प्रकरण ही नहीं, बल्कि चार वर्षों की प्रशासनिक देरी भी जांच के दायरे में आ सकती है।

क्या व्यवस्था भी लिप्त है

भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं, बल्कि समय पर सजा है। यदि रंगे हाथों पकड़े गए मामलों में भी फाइलें वर्षों तक धूमती रहें, तो सवाल केवल एक अधिकारी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का बन जाता है। जनता जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सचमुच निर्णायक है या फिर कार्रवाई केवल ट्रैप और प्रेस व्हिप्लिट तक सीमित रह जाती है।

सिर्फ गिरफ्तारी से खत्म नहीं होती लड़ाई

मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य केवल ट्रैप कर सुखिया बटोरना नहीं होना चाहिए। यदि रंगे हाथों पकड़े गए मामलों में भी वर्षों तक चालान और विभागीय कार्रवाई पूरी नहीं होती, तो जनता का भरोसा जांच एजेंसियों और शासन—दोनों से उठने लगता है।

कठघरे में ‘जिरो टॉलरेंस’

सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर ‘जिरो टॉलरेंस’ की बात करती है। लेकिन कटनी प्रकरण अब पूछ रहा है: चार साल तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या भ्रष्टाचार के मामलों में भी अलग-अलग पैमाने हैं? क्या देरी के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी? क्या मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे?

पार्किंग समस्या

क्या समदंडिया मॉल प्रबंधन के सामने नतमस्तक हो गया नगर निगम ?

बेसमेंट में पार्किंग तो सड़क पर पेड पार्किंग क्यों.... ?

हरिभूमि, जबलपुर। सिविक सेंटर स्थित समदंडिया मॉल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मॉल की स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा, जबकि आम नागरिकों को सड़क पर पेड पार्किंग का शुल्क चुकाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सार्वजनिक सड़क पर पार्किंग संचालित हो रही है तो उसकी वैधानिक मंजूरी किस विभाग ने दी है? जानकारों का कहना है कि यदि भवन अनुज्ञा में पर्याप्त पार्किंग का प्रावधान था, तो उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यदि स्वीकृत बेसमेंट पार्किंग का किसी अन्य व्यावसायिक उपयोग में इस्तेमाल किया जा रहा है या वहां से व्यावसायिक लाभ लिया जा रहा है, तो इसकी जांच आवश्यक है। इसी तरह यदि स्वीकृत योजना में बहुस्तरीय (मल्टी स्टोरी) पार्किंग का प्रावधान था, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उसका निर्माण क्यों नहीं हुआ।



सबसे अधिक सवाल नगर निगम की कार्यपाली पर उठ रहे हैं। शहर में छोटे-छोटे अतिक्रमण और नियम उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करने वाला निगम इस मामले में अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया? क्या प्रभावशाली लोगों के मामलों में नियमों का पालन अलग तरीके से कराया जाता है? यदि सार्वजनिक सड़क पर पेड पार्किंग बिना सक्षम अनुमति संचालित हो रही है, तो इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि नगर नियोजन और सार्वजनिक भूमि के उपयोग पर भी गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

निगम की अनदेखी

बड़े सवाल

- ▶ क्या सड़क पर पेड पार्किंग के लिए नगर निगम या यातायात पुलिस ने कोई वैधानिक अनुमति जारी की है?
- ▶ भवन अनुज्ञा में कितने पार्किंग स्पॉट स्वीकृत किए गए थे और वर्तमान में उनका उपयोग किस रूप में हो रहा है?
- ▶ क्या बेसमेंट की पूरी पार्किंग आज भी पार्किंग के लिए उपलब्ध है?
- ▶ यदि मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रावधान था तो उसका निर्माण क्यों नहीं हुआ?
- ▶ नगर निगम ने अब तक कितने निरीक्षण किए और उनकी रिपोर्ट क्या कहती है?
- ▶ यदि निगमों का उल्लंघन मिला है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?



यात्रियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं अनधिकृत गतिविधियों से मुक्त रेल यात्रा का वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश सगर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर एवं प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से वॉर्डिंग करते हुए कई व्यक्तियों को देखा गया। इस पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने तत्काल मुख्य टिकट निरीक्षक (सीटीआई) को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देशानुसार टिकट जांच स्टाफ की टीम ने अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए 22 अवैध वेंडरों को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान 18 अवैध वेंडरों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए ₹2,000

प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल ₹36,000 का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया गया। वहीं 4 वेंडरों द्वारा जुर्माना जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु चार्जशीट तैयार की गई। यह कार्रवाई रेलवे स्टेशन परिसर में अनुशासन बनाए रखने, यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत वॉर्डिंग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जबलपुर रेल मंडल द्वारा इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।



3420 मामलों में 34.81 करोड़ की चपत

साइबर टगी का हॉटस्पॉट बन रहा जबलपुर

जबलपुर। ऑनलाइन टगी और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों ने जबलपुर में चिंता बढ़ा दी है। आई4सी और एनसीआरपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में जबलपुर में साइबर धोखाधड़ी की 3420 शिकायत दर्ज हुई, जिनमें लोगों को करीब 34.81 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। लगातार बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।

पूरे मध्यप्रदेश में भी साइबर टगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। वर्ष 2025 में प्रदेश में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की 55,659 शिकायतें दर्ज हुईं, जिसमें करीब 581 करोड़ रुपए की टगी सामने आई। हालांकि पुलिस और साइबर टीमों की त्वरित कार्रवाई से 137 करोड़ रुपए से अधिक की राशि फ्रीज कर लोगों को राहत दिलाई गई।

निवेश ऑफर और डिजिटल असेट के नाम पर टगी.....बजाज फाइनेंस की “नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड”



जागरूकता मुहिम के दौरान जबलपुर साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन टगी के नए तरीकों से सावधान किया। साइबर क्राइम सीएसपी अंजुल मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले फर्जी निवेश ऑफर, कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच और अनजान लिंक लोगों को बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि साइबर टगी का शिकार होने पर शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करनी चाहिए। समय पर शिकायत मिलने से टगी की रकम को रोकने और

वापस दिलाने की संभावना बढ़ जाती है।साइबर क्राइम थाना प्रभारी भावना तिवारी ने लोगों को मोबाइल सुरक्षा के प्रति सतर्क करते हुए कहा कि किसी भी अनजान नंबर, ई-मेल या सोशल मीडिया अकाउंट से आए लिंक, ऐप या एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि गलती से कोई संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड हो जाए तो तुरंत इंटरनेट बंद कर देना चाहिए या फोन को फ्लाइट मोड पर डाल देना चाहिए, ताकि साइबर अपराधी डिवाइस का गलत इस्तेमाल न कर सकें।

फर्जी लोन, ओटीपी के जाल में फंस रहे लोग.....साइबर अपराधी अब पारंपरिक तरीकों के साथ हाईटेक हथकंडे अपना रहे हैं। फिशिंग लिंक, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी नौकरी के ऑफर, नकली लोन स्कीम, निवेश योजनाओं में भारी रिटर्न का झांसा, फर्जी पहचान और डिजिटल असेट जैसे तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है।

बजाज फाइनेंस के प्रतिनिधि ने बताया कि कंपनी की ओर से साइबर सुरक्षा को लेकर देशभर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, जबलपुर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर नीरज नेगी, साइबर अधिकारी अजीत गौतम, सेवानिवृत्त सीएसपी अशोक तिवारी सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। कॉलेज की प्राचार्या डॉ. निधि खन्ना, उप-प्राचार्या श्रीमती प्रजापति, छात्र-छात्राओं और फैकल्टी सदस्यों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।



हनुमानताल वार्ड को 87 लाख के विकास कार्यों की सौगात, गोविंदगंज स्कूल में बनेगे चार नए कक्ष
जबलपुर। हनुमानताल वार्ड में शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए नगर निगम द्वारा 87 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। नगर निगम गोविंदगंज स्कूल में अतिरिक्त कक्षा के निर्माण के साथ क्षेत्र में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य कराए जाएंगे। कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अज्यू, उत्तर-मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय, निगमाध्यक्ष रिकुंज विज, एम.आई.सी सदस्य एवं लोककर्म प्रमारी विवेकराम सोनकर, सामान्य प्रशासन शिक्षा प्रमारी डॉ. सुभाष तिवारी, पार्षद श्रीमती कविता रैकवार, प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्राएं घंघर गरिफ उपस्थित रहे। महापौर ने कहा कि नगर निगम स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम के बच्चे अब अपनी प्रतिभा से कॉन्वेंट स्कूलों के विद्यार्थियों को टक्कर दे रहे हैं। महापौर गुरुकुल के माध्यम से प्रतिभागी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि गोविंदगंज स्कूल में छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार नए आधुनिक कक्षा का निर्माण कराया जा रहा है। विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने कहा कि गोविंदगंज स्कूल का गौरवशाली इतिहास रहा है और यहां से पढ़कर निकली छात्राओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। नए कक्षा के निर्माण से छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। निगमाध्यक्ष रिकुंज विज ने इसे विद्यालय के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य डॉ. शैलेन्द्र पाण्डेय ने विद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर राजनीकांत अग्रवाल, गोविंद रैकवार, संतोष लालबागी, राजेश ठाकुर, विजय यादव, राकेश अग्रवाल, श्रीमती आशा मिश्रा सहित शिक्षकगण एवं नागरिक उपस्थित रहे।

खेत में बने कमरे में रखी 5 किंवदंतल मूंग दाल चोरी

जबलपुर। खमरिया थाना अंतर्गत ग्राम उमरिया स्थित एक खेत में बने कमरे से करीब 5 किंवदंतल मूंग चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि चोर दवाजे के ऊपर बने होल से कमरे में घुसकर मूंग चोरी कर ले गया है। खमरिया पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुगनी बस्ती रांझी निवासी 45 वर्षीय किसान ज्ञानेश्वर शर्मा पिछले करीब आठ वर्षों से मदनमहल निवासी उस्मान खान की ग्राम उमरिया स्थित लगभग पांच एकड़ जमीन सिकमी पर लेकर खेती कर रहा है। खेत में फसल रखने और रहने के लिए पांच कमरे बने हुए हैं, जहां पर उड़द की फसल की गहाई कराने के बाद उसने उड़द और मूंग कमरे में रखी थी। 28 जून की शाम वह घर चला गया। अगले दिन सुबह खेत पहुंचकर कमरे का ताला खोला तो मूंग की मात्रा कम दिखाई दी। उसने देखा कि दरवाजे के ऊपर लगभग डेढ़ फुट के खुले हिस्से के पास मूंग के दाने बिखरे मिले। लगभग 4 से 5 किंवदंतल मूंग चोर चोरी कर ले गया, जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये है। गत दिवस उसे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि गोकलपुर निवासी विक्की कंधे पर बोरी रखकर उसके खेत की ओर से जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी दरवाजे के ऊपर बने खुले हिस्से से कमरे के अंदर घुसा और करीब 5 किंवदंतल मूंग चोरी कर ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 331(4) एवं 305(ए) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

साहू समाज ने किया सांसद विवेक का सम्मान



सिहोरा। छिंदवाड़ा सांसद विवेक (बंटी) साहू द्वारा मंहर तक निकाली जा रही धार्मिक पदयात्रा के सिहोरा आगमन पर साहू समाज सिहोरा-खितौला एवं मझौली द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। समाजजनों ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ सांसद साहू का अभिनंदन करते हुए उन्हें शाल, श्रीफल, माला एवं पुष्पगुच्छ भेंट

किए। इस अवसर पर विधायक संतोष बरकड़े, अनुपम सराफ, राजेश दाहिया, साहू समाज सिहोरा अध्यक्ष अमित साहू, सगोड़ी सरपंच दीपक साहू, सचिन साहू, विजय साहू, अजय साहू, राजेंद्र साहू, अरविंद साहू, अजय साहू (आश्रम सरपंच), राकेश साहू, योगी साहू, हिमांशु साहू, किशोरी लाल साहू, प्रिंस साहू, मनोज साहू,

सतीश साहू, आंचल साहू, धर्मेन्द्र साहू, दिनेश साहू, दीपक साहू सहित समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। महिला अध्यक्ष अंशुल साहू, साधना साहू, सारिका साहू, मनीषा साहू, कृष्णा सरावगी तथा पार्षद ज्योति चक्रवर्ती, गीता पटेल, वर्षा ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सांसद साहू का स्वागत किया।



सिहोरा। खितौला बाजार से मंडी गेट तक सीसी रोड एवं नाला निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद राजेश चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने मंडी गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए और सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि टेंडर होने के चार माह बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ है, जिससे विद्यार्थियों, किसानों और आम

लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों की समस्या को लेकर करीब तीन घंटे तक धरना दिया गया और खितौला नगर जाने वाले मार्ग को जाम किया गया। नगर पालिका अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से प्रदर्शनकारी नाराज होकर नेशनल हाईवे पर धरना देने पहुंचे। बाद में थाना प्रभारी की पहल पर नगर पालिका अधिकारियों ने धरना स्थल पहुंचकर समस्या के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने आंदोलन समाप्त किया।

प्रदर्शन में मंजू मिश्रा, अमोल चौरसिया, प्रकाश कुररिया, बाबा कुंरेशी, पवन सोनी, पार्षद रमेश पटेल, माधुरी गणेश दाहिया, ममता गोठिया, राजेश पटेल, रामलोचन कोल, लाल बहादुर पाठक, सुभाष यादव, संतोष पांडे, अजय पाठक, जितेंद्र तिवारी, फैज आलम शाह, रमा चौरसिया, संदीप शुक्ला, मनू शुक्ला, प्रॉजल सराफ, सचिन श्रीवास्तव, रिकू शर्मा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।

पश्चिम मध्य रेल की यात्री आय में 8.22 प्रतिशत की वृद्धि, पहली तिमाही में 685 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में यात्री यातायात से 685 करोड़ 83 लाख रुपये का ऑरिजिनेटिंग राजस्व अर्जित किया है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में प्राप्त 633 करोड़ 76 लाख रुपये की तुलना में 8.22 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में आरक्षित एवं अनारक्षित सहित कुल 306 लाख 67 हजार यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 प्रतिशत अधिक है। मंडलवार राजस्व में जबलपुर मंडल ने 267 करोड़ 21 लाख रुपये, भोपाल मंडल ने 267 करोड़ 77 लाख रुपये तथा कोटा मंडल ने 150 करोड़ 84 लाख रुपये का योगदान दिया। अकेले जून माह में पश्चिम मध्य रेल ने 228 करोड़ 88 लाख रुपये यात्री आय अर्जित की, जो पिछले वर्ष जून की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है। यात्री सुविधाओं और राजस्व वृद्धि के लिए पश्चिम मध्य रेल द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन, अतिरिक्त कोच की व्यवस्था, ठहराव अवधि में वृद्धि, आईसीएफ कोच को एलएचबी में बदलने, ट्रेनों की गति बढ़ाने एवं समयपालन सुधार जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। रेल प्रशासन ने बताया कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और यात्री आय में निरंतर वृद्धि के लिए ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।

अनिल उसरेटे बने नगर अध्यक्ष

जबलपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति मप्र (राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति रजि. से सम्बद्ध) द्वारा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आलोक चंसीरिया द्वारा अनिल उसरेटे को नगर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश महासचिव सचिव अरुण सिंह ने बधाई दी।



भोंगाद्वार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अपर आयुक्त ने किया निरीक्षण, पेयजल व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश

जबलपुर। शहर में स्वच्छ एवं निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान ने भोंगाद्वार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली, जल शोधन प्रक्रिया और वितरण व्यवस्था का बारीकी से जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त ने रॉ-वाटर पंपिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का भी निरीक्षण कर पानी की शुद्धता एवं मानकों के अनुरूप जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त ने कहा कि भोंगाद्वार प्लांट शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए इसके संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित जल परीक्षण, सभी क्षेत्रों में पर्याप्त दबाव के साथ समय पर जल आपूर्ति तथा बिजली कटौती एवं तकनीकी खराबी की स्थिति में बैकअप व्यवस्था को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्लांट में कार्यरत अधिकारियों एवं तकनीकी स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि जल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।



मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभाजन पर मचा घमासान

जबलपुर की साख बचाने एकजुट होने की अपील

जबलपुर। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के संभावित विभाजन को लेकर जबलपुर में विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इसे शहर की प्रतिष्ठा और पहचान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा है कि यदि मेडिकल यूनिवर्सिटी का विभाजन किया गया तो इससे जबलपुर की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मंच ने सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से एकजुट होकर इस प्रस्ताव का विरोध करने की अपील की है।

मंच के अध्यक्ष डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने बताया कि विधायक लखन घनघोरिया ने विधानसभा सचिवालय में प्रश्न लगाकर उपमुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभाजन



के संबंध में जवाब मांगा है। इस प्रश्न का उत्तर 22 जुलाई को विधानसभा में दिया जाना प्रस्तावित है, जिससे इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। डॉ. नाजपांडे का कहना है कि जानकारी मिली है कि अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के

विभाजन के संबंध में आवश्यक सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। जिस प्रकार से प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो रही है, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा मानसून सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपभोक्ता मंच ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी

सड़क और नाला निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद राजेश चौबे ने दिया धरना, आशवासन के बाद प्रदर्शन समाप्त



सिहोरा। खितौला बाजार से मंडी गेट तक सीसी रोड एवं नाला निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद राजेश चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने मंडी गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए और सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि टेंडर होने के चार माह बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ है, जिससे विद्यार्थियों, किसानों और आम

लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों की समस्या को लेकर करीब तीन घंटे तक धरना दिया गया और खितौला नगर जाने वाले मार्ग को जाम किया गया। नगर पालिका अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से प्रदर्शनकारी नाराज होकर नेशनल हाईवे पर धरना देने पहुंचे। बाद में थाना प्रभारी की पहल पर नगर पालिका अधिकारियों ने धरना स्थल पहुंचकर समस्या के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने आंदोलन समाप्त किया।

प्रदर्शन में मंजू मिश्रा, अमोल चौरसिया, प्रकाश कुररिया, बाबा कुंरेशी, पवन सोनी, पार्षद रमेश पटेल, माधुरी गणेश दाहिया, ममता गोठिया, राजेश पटेल, रामलोचन कोल, लाल बहादुर पाठक, सुभाष यादव, संतोष पांडे, अजय पाठक, जितेंद्र तिवारी, फैज आलम शाह, रमा चौरसिया, संदीप शुक्ला, मनू शुक्ला, प्रॉजल सराफ, सचिन श्रीवास्तव, रिकू शर्मा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।

जुए के फड़ों पर छापा, 12 जुआड़ी गिरफ्तार

जबलपुर। आधारताल पुलिस ने नेता कालोनी मिलन आटा चक्की के पास बिजली खंबे के नीचे और खेरमाई मंदिर के पीछे एक जुए के फड़ पर छापा मारकर 12 जुआड़ियों को गिरफ्तार कर उसके पास से नगद 5 हजार 750 रुपए जब्त किए हैं। आधारताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि गत रात मुखबिर की सूचना पर नेता कालोनी मिलन आटा चक्की के पास बिजली खंबे के नीचे उजाले में जुआ मन्ना खसि रहें मोह. गुलजार, मोह. आमीन, मोह. मोहसिन, आसिफ मंसूरी, आशीष शुक्ला, मोह. शहजाद को गिरफ्तार कर उनके पास से नगद 2 हजार 950 रुपये जप्त किए हैं। इसी प्रकार नेता कालोनी में खेरमाई मंदिर के पीछे दबिश देते हुये साबिर खान, इमरान, जाहिद मंसूरी, मोह. शाहरुख, मेहताब खान, अनवर हुसैन को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 हजार 800 रुपये जप्त किए हैं। पुलिस ने सभी जुआड़ियों के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

श्री मारियो पीटर -गंगा मैया,

व्हीएफके निवासी श्री मारियो पीटर (बबलू) का 61 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया है. उनकी अंतिम यात्रा दिनांक 11.07. 26 को दोपहर 1:00 बजे उनके निज निवास से बिलहरी कब्रिस्तान प्रस्थान करेगी. वहां दोपहर 2:00 बजे पवित्र मिस्सा संपन्न होगा। श्री किशन सिंह राजपूत- कैलाशपुरी गुप्तेश्वर निवासी श्री किशन सिंह राजपूत (70) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गुप्तेश्वर मोक्षधाम में संपन्न हुआ। श्री सुमित चौधरी- लाल बहादुर शास्त्री वार्ड डॉ. पंचौरी के निकट निवासी श्री भारत चौधरी के पुत्र श्री सुमित चौधरी (19) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर शमशान भूमि में किया गया। श्री आर रमैया- ज्ञान विहार आदर्श नगर नर्मदा रोड निवासी श्री आर रमैया (91) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री नारायण नायर- शीतलामाई निवासी श्री नारायण नायर (71) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर शमशान भूमि में किया गया। श्रीमती कलावती यादव- सेठी नगर निवासी श्री चुनौलाल यादव की धर्मपत्नी श्रीमती कलावती

रंगदारी वसूलने चाकूबाजी की वारदात में 2 घायल

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत बड़ा पत्थर में शराब पीने के लिए रुपए नहीं मिलने की बात पर दो बदमाशों ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। रांझी पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम उमरिया डिरहा मझौली निवासी 42 वर्षीय पंजी कोल गत दिवस विकटोरिया में भर्ती अपने साले अनिल कोल को देखने के बाद साले के घर बड़ा पत्थर रांझी आया और खाना खाने के बाद बीड़ी लेने गया जहां पर वीरेंद्र कोल एवं सुक्कू कोल उससे शराब पीने के लिए 500 रुपए की मांग करने लगे, मना करने पर दोनों ने मारपीट कर वीरेंद्र ने चाकू से हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आए शंकर गोठिया पर भी सुक्कू कोल ने चाकू से हमला कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 296(बी), 119(1), 351(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

श्री मारियो पीटर -गंगा मैया,

व्हीएफके निवासी श्री मारियो पीटर (बबलू) का 61 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया है. उनकी अंतिम यात्रा दिनांक 11.07. 26 को दोपहर 1:00 बजे उनके निज निवास से बिलहरी कब्रिस्तान प्रस्थान करेगी. वहां दोपहर 2:00 बजे पवित्र मिस्सा संपन्न होगा। श्री किशन सिंह राजपूत- कैलाशपुरी गुप्तेश्वर निवासी श्री किशन सिंह राजपूत (70) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गुप्तेश्वर मोक्षधाम में संपन्न हुआ। श्री सुमित चौधरी- लाल बहादुर शास्त्री वार्ड डॉ. पंचौरी के निकट निवासी श्री भारत चौधरी के पुत्र श्री सुमित चौधरी (19) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर शमशान भूमि में किया गया। श्री आर रमैया- ज्ञान विहार आदर्श नगर नर्मदा रोड निवासी श्री आर रमैया (91) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री नारायण नायर- शीतलामाई निवासी श्री नारायण नायर (71) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर शमशान भूमि में किया गया। श्रीमती कलावती यादव- सेठी नगर निवासी श्री चुनौलाल यादव की धर्मपत्नी श्रीमती कलावती

हरिभूमि
विजी/श्रेक/उरावन, पयड़ी रम, पुष्पति
संवंधी संदेश प्रकाशित कराने के लिए
अप काल
400/-
पति काल
पति काल

विजय राहुज:- 888 से.मी. 2000/-
विजय राहुज:- 888 से.मी. 2000/-
विजय राहुज:- 888 से.मी. 2000/-

सम्पर्क करें विज्ञापन विभाग:- 9303808294, 9407362160

अब नहीं रुकेगी 1600 सीरीज की कॉल! ट्राई ने जारी किए नए नियम

एजेंसी ►► नई दिल्ली

दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुक्रवार को कहा कि 1600 नंबर श्रृंखला से आने वाली कॉल को कोई भी मोबाइल ऐप ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉल सरकार एवं विनियमित संस्थाओं की तरफ से आम लोगों के साथ संवाद के लिए निर्धारित हैं।

इसके साथ ही ट्राई ने कहा कि 140 नंबर श्रृंखला से आने वाली कॉल को केवल ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ (डीएनडी) पंजीकरण के जरिए ही ब्लॉक किया जा सकता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पष्ट किया कि दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर) के तहत 1600 श्रृंखला से आने वाली कॉल को टैग, ब्लॉक या फिल्टर करने की अनुमति नहीं है।

खबर संक्षेप

इंडियन बैंक के लाभ में 10 प्रतिशत का इजाफा



नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 को पहली तिमाही अप्रैल-जून में 10 प्रतिशत बढ़कर 3,273 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चेन्नई के इस बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की इसी तिमाही में 2,973 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

एचएफसीएल को डेटा सेंटर कंपनी से मिला निर्यात ठेका



नई दिल्ली। घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माता एचएफसीएल को एक अंतरराष्ट्रीय डेटा सेंटर कंपनी से ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित डेटा सेंटर संपर्क समाधान की आपूर्ति के लिए 495.80 करोड़ रुपये का निर्यात ठेका मिला है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस ठेके को दिसंबर, 2026 तक पूरा किया जाना है।

रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 95.33 प्रति डॉलर पर



मुंबई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में शुक्रवार को रुपया 14 पैसे चढ़कर 95.33 प्रति डॉलर पर रहा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कमजोर होते डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये को समर्थन मिला। पूंजी निकासी और पश्चिम एशिया में नए सिर्रे से तनाव को लेकर अनिश्चितता बढ़ने का स्थानीय मुद्रा पर दबाव रहा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लाभ 27 प्रतिशत बढ़ा



नई दिल्ली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में 27 प्रतिशत बढ़कर 2,020 करोड़ रुपये हो गया। बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुणे स्थित बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की इसी तिमाही में 1,593 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

आनंद राठी वेलथ के लाभ में 24 फीसदी की बढ़त



नई दिल्ली। आनंद राठी वेलथ का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में 24 प्रतिशत बढ़कर 116 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की कुल प्रबंधीन अधीन परिसंपत्ति और ग्राहकों की संख्या में लगातार वृद्धि से उसके प्रदर्शन को मजबूती मिली है। 2025-26 की जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 93.8 करोड़ रुपये था। 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में उसकी कुल आय 18 प्रतिशत बढ़कर 336.4 करोड़ रुपये हो गई।

कोई भी मोबाइल ऐप इस सीरीज को ब्लॉक नहीं कर सकता

1600 सीरीज का उपयोग आरबीआई, सेबी, इरडा आदि करती है : ट्राई के मुताबिक, 1600 नंबर श्रृंखला का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) और पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) जैसे नियामकों के अधीन आने वाली बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा कंपनियों अपने ग्राहकों से सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल के लिए करती हैं।

140 की सीरीज टेलीमार्केटिंग कंपनियों उपयोग करती है

इसके साथ ही ट्राई ने कहा कि 140 नंबर श्रृंखला का उपयोग पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों द्वारा प्रचार संबंधी कॉल के लिए किया जाता है। इन कॉल को किसी ऐप के माध्यम से टैग या फिल्टर नहीं किया जा सकता और इन्हें केवल 'डू नॉट डिस्टर्ब' (डीएनडी) पंजीकरण के जरिए ही ब्लॉक किया जा सकता है।



सरकारी संस्थाएं भी इसी सीरीज का उपयोग करती हैं: इसके अलावा, सरकारी संस्थाएं भी नागरिकों से संवाद के लिए इसी फ़ोन नंबर श्रृंखला का इस्तेमाल करती हैं। उद्देश्य इन्हें नागरिकों के लिए अधिक विश्वसनीय बनाना है।

140 सीरीज में डीएनडी का पंजीकरण हो सकता है

प्राधिकरण ने कहा, "ट्राई डीएनडी ऐप सहित विभिन्न माध्यमों से 'डू नॉट डिस्टर्ब' (डीएनडी) पंजीकरण कराया जा सकता है। जहां तक 140 श्रृंखला की कॉल का सवाल है तो उसे टैग या फिल्टर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे उन उपभोक्ताओं को अम हो सकता है जिन्होंने किसी क्षेत्र से कॉल की अनुमति दी हुई है।

प्रचार कॉल को अनुमति दे सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं : नियामक के अनुसार, उपभोक्ता डीएनडी रजिस्ट्री पर अपनी पसंद दर्ज कर किसी एक या सभी क्षेत्रों से आने वाली प्रचार कॉल को अनुमति दे सकते हैं या उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। यदि किसी उपभोक्ता ने किसी क्षेत्र की कॉल ब्लॉक कर दी है, तो उसे उस क्षेत्र से 140 श्रृंखला की कोई भी कॉल नहीं आएगी।

मंत्रालय ने एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम की आलोचनाओं का दिया जवाब

ई20 से पांच प्रतिशत घट सकती है माइलेज लेकिन स्वच्छ दहन जैसे लाभ अधिक: मंत्रालय

एजेंसी ►► नई दिल्ली

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) के इस्तेमाल से कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता (माइलेज) तीन से पांच प्रतिशत तक कम हो सकती है, लेकिन इसके बदले मिलने वाले ऊर्जा सुरक्षा, कम कार्बन उत्सर्जन और बेहतर इंजन प्रदर्शन जैसे लाभ कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

मंत्रालय के अनुसार, इसके अलावा ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर एंटी-नॉक क्षमता, तेज दहन, बेहतर पिकअप आदि जैसे लाभ भी इसमें शामिल हैं। एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईसीपी) कार्यक्रम की आलोचनाओं का जवाब देने के लिए जारी प्रश्नोत्तर दस्तावेज में मंत्रालय ने कहा कि ई20, ई10 या शुद्ध पेट्रोल की तुलना में "अधिक स्वच्छ, बेहतर गुणवत्ता वाला और अधिक दक्ष ईंधन है।"

कलपुर्जो खराब होने की कोई शिकायत नहीं मिली

मंत्रालय ने कहा कि मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प सहित वाहन विनिर्माताओं से मिली प्रतिक्रिया के अनुसार, वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग किए गए वाहनों में ई20 के कारण जंग लगने, असामान्य धिमाव या कलपुर्जों के जल्दी खराब होने की कोई शिकायत नहीं मिली है।



जरूरी नहीं की पेट्रोल से ई20 सस्ता हो

कीमतों के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि ई20 जरूरी नहीं कि पारंपरिक पेट्रोल से सस्ता हो, क्योंकि किसानों को समर्थन देने के लिए एथनॉल की खरीद कोमत लाभकारी स्तर पर तय की जाती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने पर यह पेट्रोल से भी महंगा पड़ सकता है।

- कुछ वाहनों में ईंधन क्षमता तीन से पांच फीसदी तक घट सकती है
- पेट्रोल की तुलना में अधिक स्वच्छ, गुणवत्ता वाला और दक्ष है
- मंत्रालय ने यह आशंका खारिज की कि कार्यक्रम जल्दबाजी में लागू किया गया

पुराने वाहनों पर भी व्यापक परीक्षण

पुराने वाहनों को लेकर उठी चिंताओं पर मंत्रालय ने कहा कि ई20 को देशभर में लागू करने से पहले इंजन की टिकाऊ क्षमता, ईंधन प्रणाली, विभिन्न सामग्रियों के साथ अनुकूलता, जंग-रोधी क्षमता, वाहन संचालन और उत्सर्जन सहित अनेक पहलुओं पर व्यापक परीक्षण किए गए।

कई प्रकार के ईंधन उपलब्ध करने की मांग की खारिज : मंत्रालय ने पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल, ई10 और ई20 जैसे कई प्रकार के ईंधन उपलब्ध कराने की मांग को भी खारिज करते हुए कहा कि पूरे देश में समानांतर आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने से लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ेगी और एक लाख से अधिक सुकुरा ईंधन केंद्रों पर वितरण व्यवस्था जटिल हो जाएगी।

एनसीडीईएक्स ने काली मिर्च वायदा कारोबार फिर किया शुरू

एजेंसी ►► मुंबई

जिंस बाजार एनसीडीईएक्स ने काली मिर्च (ब्लैक पेपर) के वायदा कारोबार को फिर शुरू करने की घोषणा की है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस कदम का उद्देश्य भारत को इस मसाले के वैश्विक मूल्य निर्धारण का प्रमुख केंद्र बनाना है। एनसीडीईएक्स ने कहा कि एक दशक से अधिक समय बाद काली मिर्च वायदा अनुबंध की वापसी से इस जिंस के लिए भारत में फिर से पारदर्शी मूल्य निर्धारण व्यवस्था उपलब्ध होगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े काली मिर्च उत्पादकों, उपभोक्ताओं और प्रसंस्करण केंद्रों में शामिल है, लेकिन वर्तमान में इस जिंस के लिए दुनिया में कोई सक्रिय वायदा मानक उपलब्ध नहीं है। एनसीडीईएक्स ने बताया कि इस वायदा अनुबंध का डििलीवरी केंद्र केरल का कोच्चि होगा, जो देश में मसालों के प्रमुख व्यापार एवं प्रसंस्करण केंद्रों में शामिल है।

भारत की स्थिति मजबूत होगी

सीओ ने कहा कि मजबूत डेरिवेटिव बाजार से किसानों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और व्यापारियों को कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी और वैश्विक मसाला कारोबार में भारत की स्थिति मजबूत होगी।



- भारत को मसाले के वैश्विक मूल्य निर्धारण का प्रमुख केंद्र बनाना
- एक दशक से अधिक समय के बाद काली मिर्च का अनुबंध शुरू

नई व्यवस्था के तहत कारोबार को एक इकाई एक टन (1,000 किलोग्राम) होगी।

एनसीडीईएक्स ने कहा कि पहले जब काली मिर्च वायदा अनुबंध का कारोबार होता था, तब किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और प्रसंस्करण इकाइयों की इसमें अच्छी भागीदारी रहती थी। अनुबंध की समाप्ति पर डििलीवरी का अनुपात लगभग 100 प्रतिशत रहता था।

इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुद्ध निवेश जून में 26% बढ़ा

एजेंसी ►► नई दिल्ली

शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच इक्विटी यानी शेयर में निवेश से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं में जून के दौरान शुद्ध निवेश 26 प्रतिशत बढ़कर 28,973 करोड़ रुपये रहा।

म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एस्फी) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। हालांकि, बॉन्ड आधारित योजनाओं से 1.09 लाख करोड़ रुपये की निकासी के कारण जून में म्यूचुअल फंड उद्योग से कुल 52,949 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी दर्ज की गई। यह मई में हुई 64,131 करोड़



- जून के दौरान शुद्ध निवेश 28,973 करोड़ रुपए रहा
- बांड आधारित योजनाओं से 1.09 लाख करोड़ रुपए की निकासी हुई

जानवरी में 24,028 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया था।

सोने में 400 रुपए की तेजी, चांदी 5,000 रुपए मजबूत

एजेंसी ►► नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 400 रुपये बढ़कर 1,48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत में 5,000 रुपये का उछाल आया।

तेजी का कारण कारोबारियों के नीचे मूल्य पर लिवाली और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी रख के बाद कीमती धातुओं की मांग में आई तेजी थी। इससे पहले के सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ



- सोने की कीमत बढ़कर 1,48,500 रुपए प्रति दस ग्राम
- चांदी बढ़कर हुई 2,37,000 रुपए प्रति किलोग्राम

था। चांदी ने भी लगातार तीन सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ा और बृहस्पतिवार के 2,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बंद स्तर से 5,000 रुपये बढ़कर 2,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गई। यह सुधार डॉलर सूचकांक के लगातार तीसरे सत्र में कमजोर होने की वजह से आई, जिससे कीमती धातुओं की मांग बढ़ी। साथ ही, इस हफ्ते की शुरुआत में सोने की कीमत एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने कम कीमतों का फायदा उठाते हुए लिवाली की।

नवीन जितल समूह झारखंड में 70 हजार करोड़ करेगा निवेश



नई दिल्ली। उद्योगपति नवीन जितल ने झारखंड में इस्पात, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने की शुक्रवार को घोषणा की। जितल ने वीडियो संदेश में कहा कि इस संबंध में समूह ने झारखंड सरकार के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

मुझे यह घोषणा करते हुए काफी खुशी हो रही है कि नवीन जितल समूह ने राज्य में इस्पात, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निवेश में इस्पात क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

इस सीरीज की फर्जी कॉल में काफी वृद्धि हुई

ट्राई के इस स्पष्टीकरण का मतलब है कि उपभोक्ता 1600 और 140 नंबर श्रृंखला से आने वाली कॉल को 'स्पेम' या 'फ्रॉड' के रूप में चिह्नित नहीं कर पाएंगे। इस बीच, कॉलर की पहचान करने वाले ऐप 'ट्रूकॉलर' के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ऋषित झुनझुनवाला ने कहा कि 140 और 1600 श्रृंखला से आने वाली फर्जी (स्पेम) कॉल में काफी वृद्धि हुई है।

5.1 करोड़ से अधिक कॉल लोग उठाते नहीं

इन दोनों श्रृंखलाओं से प्रतिदिन आने वाली 5.1 करोड़ से अधिक कॉल को लोग उठाते भी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि 1600 श्रृंखला से आने वाली कॉल को ब्लॉक करने की कार्रवाई में अक्टूबर 2025 से 208 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और पिछले आठ महीनों में इस श्रृंखला के खिलाफ 7.4 करोड़ से अधिक मैनुअल ब्लॉकिंग की गई है।

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 828 अंक उछला

एजेंसी ►► मुंबई

प्रमुख कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईआई बैंक एवं एचडीएफसी बैंक में लिवाली और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 828 अंक और निफ्टी 244 अंक के लाभ में रहा।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के जून तिमाही के बेहतर नतीजों के बाद आईटी शेयरों में आई तेजी से भी बाजार को मजबूती मिली। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 827.57 अंक उछलकर 77,569.39 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 900.41 अंक चढ़कर 77,642.23 अंक तक पहुंच गया था। निफ्टी 244.10 अंक की बढ़त के साथ 24,206.90 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और इन्फोसिस के शेयर प्रमुख रूप से बढ़त के साथ बंद हुए। देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा



- कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से बाजार को मिली मजबूती
- रिलायंस, आईसीआईआई व एचडीएफसी में रही खरीदारी

कंपनी टीसीएस का शेयर करीब एक प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ। दूसरी तरफ, इटर्नल (जैमेटो और ब्लिंकित का संचालन करने वाली), भारती एयरटेल, सन फार्मा और टैट के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

कूड़ गिरकर 76 डॉलर पर

रेलियेयर हॉकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शेयर) अर्जीत मिश्रा ने कहा, "बाजार में सरकारात्मक रुख तिमाही नतीजों के सत्र की स्थिर शुरुआत से प्रेरित रहा। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी और रखले में स्थिरता ने भी निवेशकों के झरोसे को समर्थन दिया।" वैश्विक तेल मानक बैट कूड़ 0.30 प्रतिशत गिरकर 76.07 डॉलर प्रति बैरेल पर आ गया।

टीसीएस के नतीजों से धारणा बदली

ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुडी आर ने कहा, "टीसीएस के उम्मीद से बेहतर नतीजों ने आईटी क्षेत्र को लेकर धारणा बदलने का काम किया है। बैंक, रियल्टी, धातु, तेल एवं गैस और रक्षा शेयरों में लिवाली से तेजी को समर्थन मिला।"

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7.26 अरब डॉलर बढ़ा

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार तीन जुलाई को समाप्त सप्ताह में 7.26 अरब डॉलर बढ़कर 674.19 अरब डॉलर हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.65 अरब डॉलर घटकर 666.93 अरब डॉलर रह गया था। इस साल 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने से पहले देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 728.49 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।



चिंतन

ई20 पेट्रोल से होने वाला लाभ वाहन चालकों को क्यों नहीं

सरकार ने आखिरकार वह स्वीकार कर लिया है, जिसकी चर्चा लंबे समय से वाहन उपभोक्ताओं और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के बीच होती रही थी। पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता यानी माइलेज को 3 से 5 प्रतिशत तक कम कर सकता है। सरकार का कहना है कि यह कमी बेहतर इंजन प्रदर्शन, कम प्रदूषण और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने जैसे दीर्घकालिक लाभों के सामने छोटी है। दरअसल ई20 को लेकर विवाद का केंद्र केवल माइलेज नहीं है, बल्कि यह सवाल भी है कि क्या ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना गया है कि माइलेज में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि ई20 का उद्देश्य पेट्रोल सस्ता करना नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में जैव-ईंधन (बायोफ्यूल) की ओर बढ़ना केवल पर्यावरणीय विकल्प नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है। इसी सोच के तहत वर्ष 2001 में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2022 में भारत ने निर्धारित समय से पहले 10 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया और 2025-26 में 20 प्रतिशत मिश्रण का क़दम पहुंच गया। इस कार्यक्रम से अब तक लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और लगभग 952 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है। साथ ही किसानों को एथेनॉल खरीद के माध्यम से 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हुआ है। इसने ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आय जैसे तीनों लक्ष्यों को एक साथ साधने का काम किया है। क्या इन उपलब्धियों का लाभ सीधे वाहन मालिकों तक भी पहुंच रहा है? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी वाहन का माइलेज 3 से 5 प्रतिशत कम होता है, तो वाहन चालक को समान दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन खरीदना पड़ेगा। यदि पेट्रोल की कीमत में कोई राहत नहीं मिलती और ई20 पारंपरिक पेट्रोल से सस्ता भी नहीं है, तो उपभोक्ता के लिए वास्तविक परिचालन लागत बढ़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तब एथेनॉल की लागत पेट्रोल से अधिक भी हो सकती है। इसका अर्थ है कि ई20 को केवल सस्ते ईंधन के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई20 को लेकर वाहन सुरक्षा संबंधी आशंकाएं व्यापक परीक्षणों के बाद ही दूर की गई हैं। यदि ई20 एक राष्ट्रीय रणनीति है, जिसका लाभ पूरे देश को मिलेगा तो क्या उसका आर्थिक भार केवल वाहन उपभोक्ताओं को उठाना चाहिए? क्या सरकार को कर संरचना, मूल्य निर्धारण या अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से इस अतिरिक्त लागत का कुछ हिस्सा स्वयं वहन नहीं करना चाहिए? इसी प्रकार, यदि माइलेज में कमी वैज्ञानिक तथ्य है, तो इसकी स्पष्ट जानकारी वाहन खरीदते समय उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी भी बड़े सुधार की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके क्रियावन्धन और जनता की स्वीकृति से तय होती है। यदि देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो इस यात्रा में नागरिकों का विश्वास भी उतना ही आवश्यक है जितना उनका योगदान। ऊर्जा परिवर्तन तभी टिकाऊ होगा, जब उसका लाभ और उसकी लागत दोनों समाज के सभी वर्गों के बीच संतुलित रूप से साझा किए जाएं।

जनसंख्या दिवस राजेश जैन



148 करोड़ लोग: भारत की सबसे बड़ी ताकत या चुनौती

आज के दिन 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की बढ़ती आबादी के आंकड़ों की चर्चा का अवसर बनता है, लेकिन भारत के लिए इसका महत्व इससे कहीं अधिक है। यह केवल जनसंख्या गिनने का दिन नहीं, बल्कि यह सोचने का अवसर है कि क्या देश अपनी सबसे बड़ी मानव पूंजी को विकास की ताकत बना पाएगा या यही आबादी भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। आज भारत लगभग 148 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। एक वर्ग इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति मानता है, जबकि दूसरा इसे बेरोजगारी, संसाधनों पर बढ़ते दबाव और सामाजिक असमानता की वजह मानता है। सच यह है कि आबादी अपने आप में न ताकत होती है और न बोझ। उसकी दिशा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार तय करते हैं। किसी भी देश की वास्तविक ताकत उसके नागरिकों की गुणवत्ता से तय होती है। यदि लोग शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हैं तो बड़ी आबादी आर्थिक विकास का इंजन बन जाती है। कमजोर शिक्षा, सीमित रोजगार और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था उसी आबादी को विकास में बाधा बना देती है। चीन ने दशकों तक प्रशिक्षित कार्यबल के दम पर दुनिया की फैक्ट्री बनने का गौरव हासिल किया, लेकिन आज वहां तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी नई चुनौती बन गई है। भारत की स्थिति अलग है। यहां औसत आयु लगभग 29 वर्ष है और करीब 65 प्रतिशत आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है। हमारे लिए यह जनसांख्यिकीया लाभार्श यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन यह अवसर स्थायी नहीं है। यदि आने वाले वर्षों में शिक्षा, कौशल और रोजगार पर पर्याप्त निवेश नहीं हुआ तो यही लाभार्श भविष्य में आर्थिक और सामाजिक दबाव में बदल सकता है। भारत केवल आबादी के लिहाज से बड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे आकर्षक उपभोक्ता बाजारों में भी शामिल है। यही वजह है कि वैश्विक कंपनियां भारत को अगले दो दशकों का सबसे महत्वपूर्ण बाजार मान रही हैं। डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसी पहलों ने इस क्षमता को नई गति दी है। इंटरनेट गांवों तक पहुंचा है, डिजिटल भुगतान आम हो चुका है और स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। इन उपलब्धियों के बावजूद एक बड़ी चुनौती सामने है। हर साल लाखों युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन उद्योगों को योग्य कर्मचारी नहीं मिलते और युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता। समस्या केवल नौकरियों की संख्या नहीं, बल्कि रोजगार योग्य कौशल की भी है। यहीं सरकार की नीतियों की असली परीक्षा शुरू होती है। पिछले एक दशक में नई शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गईं। इनसे नए अवसर जरूर बने हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं।

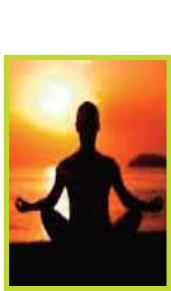
नई शिक्षा नीति कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी, डिजिटल संसाधनों का अभाव और राज्यों के बीच असमानताएं इसकी राह कठिन बनाती हैं। स्किल इंडिया ने प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाया है, लेकिन उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल अभी भी जरूरी है। स्टार्टअप इंडिया ने नवाचार को बढ़ावा दिया है, हालांकि इसका लाभ अभी मुख्य रूप से बड़े शहरों तक सीमित है। छोटे शहरों और ग्रामीण भारत को भी इस बदलाव से जोड़ना होगा। इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था अनिवार्य है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने लाखों परिवारों को राहत दी है, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता, कुपोषण और मानसिक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां अभी भी गंभीर हैं। इसी तरह महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाएं बिना भारत अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर सकता। भारत के लिए अगले 20 से 25 वर्ष निर्णायक हैं। 148 करोड़ लोगों का देश होना न उपलब्धि है और न समस्या। असली सवाल यह है कि इन लोगों में कितने शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और उत्पादक हैं। यदि भारत अपनी मानव पूंजी में सही निवेश करता है तो यही आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यदि यह अवसर चूक गया, तो यही संख्या भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यही याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके नागरिक होते हैं। भारत वह देश दुनिया की सबसे बड़ी युवा मानव पूंजी है। अब यह देश पर निर्भर है कि वह इसे विकास की सबसे बड़ी शक्ति बनाता है या एक चूके हुए अवसर में बदल देता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के निकट पालघर जिले के कोरे बीच के पास भारत का पहला ऑफ़शोर अर्थात समुद्र आधारित हवाई अड्डा विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यदि यह परियोजना निर्धारित योजना के अनुसार साकार होती है तो यह केवल एक नया एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि भारत की विमानन क्षमता, समुद्री इंजीनियरिंग, व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास का नया प्रतीक बनेगा। यह परियोजना देश को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर सकती है, जिन्होंने समुद्र से भूमि तैयार कर विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण किया है। ऑफ़शोर एयरपोर्ट का विचार अपने आप में अत्यंत आधुनिक और दूरदर्शी है। सामान्यतः हवाई अड्डे विशाल भूमि पर बनाए जाते हैं, लेकिन महानगरों में भूमि की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। बढ़ती आबादी, तेजी से फैलते शहर और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सामाजिक तथा कानूनी चुनौतियां नई परियोजनाओं को कठिन बना देती हैं। ऐसे में समुद्र के भीतर कृत्रिम भूमि तैयार कर उस पर एयरपोर्ट का निर्माण एक व्यावहारिक विकल्प बनकर उभरा है। अरब सागर में पुनः प्राप्त भूमि पर बनने वाला यह एयरपोर्ट भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता की नई पहचान बनेगा। प्रस्तावित एयरपोर्ट की क्षमता इसे विश्व के प्रमुख हवाई अड्डों की श्रेणी में ला सकती है। योजना के अनुसार यहां प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ यात्रियों के आवागमन और लगभग 30 लाख मीट्रिक टन कार्गो की आवाजाही की व्यवस्था होगी। दो समानांतर रनवे विकसित किए जाने की भी योजना है, जिससे बड़ी संख्या में विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। यह क्षमता केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों की मांग को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह परियोजना भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जा रही है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। यहां स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के बावजूद भविष्य में यात्रियों और

मुंह के मौन से ज्यादा जरूरी ‘मन का मौन’



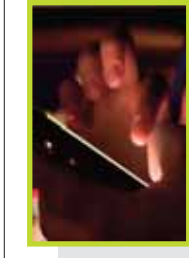
संकलित दर्शन

हम सभी मनुष्य जन्मते ही अपना मुख चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रमाण है जन्म लेते ही शिशु का रोना। बोलना हमारी स्वाभाविक क्रिया है, जो हमें करनी ही पड़ती है। यह बात और है कि कभी-कभी बाहर के शोर में हम इतने खो जाते हैं कि ईश्वर का स्वर हमें सुनाई ही नहीं पड़ता। इसीलिए ही महापुरुषों से हमें एक उत्तम राय मिलती है कि सप्ताह में या माह में एक दिन अवश्य मौन रहे, परंतु हम मुख को तो बंद कर लेते हैं, परंतु हमारे मन का बोलना बंद नहीं हो पाता। इसीलिए ही तो अधिकतर डाक्टर सभी मरीजों को कहते हैं कि ‘अपने मन को ज्यादा नहीं चलाओ।’ अर्थात ‘मन का मौन’ करो। कहते हैं कि बिना हड्डी की जीभ जब बोलने लगती है, तो कइयों की हड्डियां तोड़ देती है। इसीलिए तो हमें यह बचपन से सिखाया जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुख से निकला हुआ वचन भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है महाभारत की कथा, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक जुबान के फिसलने से संकटकाल का निर्माण हो गया। इसीलिए ‘कम बोलें-धीरे बोलें-मीठा बोलें।’ हम जब भी कुछ बोलें तो हमारे वचन दूसरों के लिए सुखदायी हों, न कि कांटा चुभाने वाले दुखदायी। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कटु वचन बोलने के संस्कार के कारण अपने संबंधों में खटास पैदा कर ली है। इसीलिए हमें सदैव सही समय और सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए।



करंट अफेयर 10 लाख महिलाओं को मदद मिलनी बंद हो गई : संरा

महिलाओं के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 18 महीनों में बजट में कटौती के कारण कम से कम 10 लाख महिलाओं को मानवीय और अन्य जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है। एजेंसी ‘यूएन वीमेन’ का कहना है कि सर्वेक्षण में शामिल 84 प्रतिशत महिला संगठनों ने बताया है कि जनवरी 2025 से उनकी जरूरतें बढ़ गई हैं। इसी समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता सभाली थी और विदेशी मदद में कटौती शुरू की थी। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता देने वाला देश है। एजेंसी की शीर्ष अधिकारी सोफिया कॉलटॉर्प ने कहा, ‘ महिलाओं के संगठनों से वापस लिया गया हर डॉलर, यौन हिंसा की शिकार महिलाओं, विस्थापित माताओं, स्कूल छोड़ने पर मजबूर लड़कियों और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे समुदायों से वापस लिया गया डॉलर है।’ सर्वेक्षण में शामिल लगभग 90 प्रतिशत महिला समूहों ने कहा कि वे अब जरूरत के मौजूदा स्तर को पूरा नहीं कर सकते, और हर पांच में से एक समूह ने कहा कि उन्हें आशंका है कि वे अगले साल कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए कामकाज बंद कर देंगे।



आर्थिक नुकसान, रिश्ते टूटने और अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पोकर मशीन और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे जुए के कुछ स्वरूप अन्य की तुलना में अधिक नुकसानदेह हैं और इनसे लत लगने की आशंका अधिक रहती है। उन्होंने कहा कि जुए से होने वाला सबसे आम नुकसान आर्थिक होता है। इसमें खर्च के लिए कम धन बचने से लेकर जीवनभर की बचत या मकान तक गंवाने जैसी गंभीर स्थितियां शामिल हैं।

समुद्र पर बनेगा भारत का हवाई अड्डा

भारत की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार उसकी आधुनिक अवसररचना है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने सड़क, रेल, बंदरगाह, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार देखा है। अब इसी शृंखला में एक और ऐतिहासिक पहल जुड़ने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के निकट पालघर जिले के कोरे बीच के पास भारत का पहला ऑफ़शोर अर्थात समुद्र आधारित हवाई अड्डा विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यदि यह परियोजना निर्धारित योजना के अनुसार साकार होती है तो यह केवल एक नया एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि भारत की विमानन क्षमता, समुद्री इंजीनियरिंग, व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास का नया प्रतीक बनेगा। यह परियोजना देश को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर सकती है, जिन्होंने समुद्र से भूमि तैयार कर विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण किया है। ऑफ़शोर एयरपोर्ट का विचार अपने आप में अत्यंत आधुनिक और दूरदर्शी है। सामान्यतः हवाई अड्डे विशाल भूमि पर बनाए जाते हैं, लेकिन महानगरों में भूमि की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है।

बढ़ती आबादी, तेजी से फैलते शहर और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सामाजिक तथा कानूनी चुनौतियां नई परियोजनाओं को कठिन बना देती हैं। ऐसे में समुद्र के भीतर कृत्रिम भूमि तैयार कर उस पर एयरपोर्ट का निर्माण एक व्यावहारिक विकल्प बनकर उभरा है। अरब सागर में पुनः प्राप्त भूमि पर बनने वाला यह एयरपोर्ट भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता की नई पहचान बनेगा। प्रस्तावित एयरपोर्ट की क्षमता इसे विश्व के प्रमुख हवाई अड्डों की श्रेणी में ला सकती है। योजना के अनुसार यहां प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ यात्रियों के आवागमन और लगभग 30 लाख मीट्रिक टन कार्गो की आवाजाही की व्यवस्था होगी। दो समानांतर रनवे विकसित किए जाने की भी योजना है, जिससे बड़ी संख्या में विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। यह क्षमता केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों की मांग को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह परियोजना भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जा रही है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। यहां स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के बावजूद भविष्य में यात्रियों और

माल परिवहन की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रस्तावित ऑफ़शोर एयरपोर्ट इस चुनौती का दीर्घकालिक समाधान बन सकता है। इससे न केवल मुंबई क्षेत्र के हवाई यातायात का दबाव कम होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और माल परिवहन के लिए भी नई संभावनाएं खुलेंगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका बहुआयामी संपर्क तंत्र है। प्रस्तावित एयरपोर्ट को वधावन बंदरगाह, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे तथा प्रस्तावित उत्तन विरार सी लिंक से जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त समर्पित माल



गलियारे और अन्य सड़क संपर्क भी विकसित किए जाएंगे। इससे हवाई, समुद्री, रेल और सड़क परिवहन का ऐसा समन्वित नेटवर्क तैयार होगा जो भारत में मल्टीमॉडल परिवहन का उत्कृष्ट उदाहरण बन सकता है। वधावन बंदरगाह स्वयं भारत की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री परियोजनाओं में गिना जा रहा है। यदि उसके साथ विशाल कार्गो क्षमता वाला एयरपोर्ट भी विकसित हो जाता है तो पश्चिमी भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नया केंद्र उभर सकता है। समुद्री मार्ग से आने वाला माल कम समय में हवाई मार्ग से देश और विदेश भेजा जा सकेगा। हवाई मार्ग से आने वाला उच्च मूल्य का सामान सीधे बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे निर्यात और आयात दोनों क्षेत्रों को गति मिलेगी तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। स्थानीय युवाओं को निर्माण, विमानन, आतिथ्य, सुरक्षा, परिवहन और तकनीकी सेवाओं में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन भी कम हो सकता है। इतनी विशाल परियोजना के साथ कई तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। समुद्र से भूमि तैयार करना अत्यंत जटिल इंजीनियरिंग कार्य है। किसी भी बड़े विकास कार्य में पर्यावरण संरक्षण और सतत

विकास के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। यदि इन पहलुओं की अनदेखी की गई तो दीर्घकाल में परियोजना को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से इस्पात, सीमेंट, मशीनरी, इंजीनियरिंग, परिवहन और निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना पूर्ण होने के बाद विमानन, पर्यटन, व्यापार, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और निर्यात आधारित उद्योगों में नई ऊर्जा आएगी। विदेशी निवेशकों के लिए भी यह क्षेत्र अधिक आकर्षक बन सकता है क्योंकि आधुनिक परिवहन अवसररचना निवेश का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। इससे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे पश्चिमी भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। भारत ने पिछले दशक में विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। छोटे शहरों तक हवाई सेवाएं पहुंचाने की योजनाओं से लेकर नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण तक अनेक प्रयास किए गए हैं। आज भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है। ऐसे समय में ऑफ़शोर एयरपोर्ट जैसी परियोजना यह संकेत देती है कि देश केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक योजना बना रहा है। हालांकि परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि योजना निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक सभी चरणों में पारदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। स्थानीय समुदायों की चिंताओं को समझना, पर्यावरणीय प्रभावों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और समयबद्ध निर्माण करना उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना स्वयं एयरपोर्ट का निर्माण। यदि इन सभी पहलुओं पर संतुलित ढंग से कार्य किया गया तो यह परियोजना केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए विकास का नया मॉडल बन सकता है। भारत आज उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां अवसररचना केवल सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का आधार बन चुकी है। पालघर के समुद्र में प्रस्तावित यह ऑफ़शोर एयरपोर्ट उसी बदलते भारत की कहानी कहता है जो सीमित संसाधनों में भी नए समाधान खोजने का साहस रखता है। यदि यह सपना साकार होता है तो यह केवल समुद्र पर बना एक हवाई अड्डा नहीं होगा, बल्कि भविष्य के भारत की दूरदृष्टि, तकनीकी क्षमता और विकास के संकल्प का जीवंत प्रतीक बनकर उभरेगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दें सकते हैं।

एक दिन का पुण्य ही क्यों

निर्जला एकादशी से अगले दिन एक भिखारी एक सज्जन की दुकान पर भीख मांगने पहुंचा। सज्जन व्यक्ति ने 1 रुपए का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया। भिखारी को प्यास भी लगी थी, वो बोला बाबूजी एक गिलास पानी भी पिचवा दो, गला सूखा जा रहा है। सज्जन व्यक्ति ने गुस्से में कहा: तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या हम यहां, पहले पैसे, अब पानी, थोड़ी देर में रोटी मांगेगा, चल भाग यहाँ से। भिखारी बोला: बाबूजी गुस्सा मत कीजिये मैं आगे कहीं पानी पी लूंगा। पर जहां तक मुझे याद है, कल आपने निकलने एकादशी व्रत का पत्र दिया था, तथा कल इसी दुकान के बाहर मोटे पानी की छबील लगी थी और आप स्वयं लोगों को रोक रोक कर जबरदस्ती अपने हाथों से गिलास पकड़ा रहे थे, मुझे भी कल आपके हाथों से दो गिलास शर्बत पीने को मिला था। मैंने तो यही सोचा था, आप बड़े धर्मात्मा आदमी है, पर आज मेरा भ्रम टूट गया। कल की छबील तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिये लगाई होगी? मुझे आज आपने कड़वे वचन बोलकर अपना कल का सारा पुण्य खो दिया। मुझे छमा करना अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो। सज्जन व्यक्ति को बात दिल पर लगी, उसकी नजरों के सामने बीते दिन का प्रत्येक दृश्य घूम गया। उसे अपनी गलती का अहसास हो रहा था। वह स्वयं अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से गिलास में पानी भरकर उस बाबा को देते हुए उसे क्षमा प्रार्थना करने लगा। भिखारी: बाबूजी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, परन्तु अगर मानवता को अपने मन की गहराइयों में नहीं बसा सकते तो एक-दो दिन किये हुए पुण्य कार्य व्यर्थ ही हैं।



संकलित प्रेरणा



भारत-न्यूजीलैंड की दोस्ती

नाट वोकल एक्सेलब की शानदार प्रस्तुति देखकर बहुत खुशी हुई। संगीत में लोगों को एक साथ लाने की अनेकछी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत-न्यूजीलैंड की दोस्ती की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से दर्शाया।

- नट्रेट मोदी, प्रधानमंत्री

रेड्डी का गणित कमजोर

मुख्यमंत्री रेंवत रेड्डी का गणित कमजोर है। वे बार-बार कहते हैं कि वेद ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस के ये लोग बस एक ही बात दोहराते हैं: वे खुद कुछ करना नहीं सकते और दूसरों का सहारा लेना बंद नहीं करेंगे! हिमाचल प्रदेश में भी वे यही करते हैं।

- जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

16 पार्षद भाजपा में शामिल

आज दिल्ली की प्रगति और जनसेवा के संकल्प को नई मजबूती मिली है। इंद्राप्रस्थ डेवलपमेंट पार्टी के सोलह पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्षदों का यह निर्णय राजधानी के विकास कार्यों को नई गति देगा।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

अप्रेंटिसशिप जरूरी

अब भारत में अप्रेंटिसशिप की बड़े पैमाने पर वापसी के लिए सही समय आ गया है। नैटवर्कपेरिफेरल हमारे लिए बहुत जरूरी है। और छात्रों व नई टेक्नोलॉजी के आने के साथ, 'काम करते हुए सीखना' ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है।

- अनिल अग्रवाल, उद्यमी

हमारा पता

हरिभूमि कार्यालय

66/1 इंडस्ट्रियल एरिया, रिहाई, जबलपुर (मप्र)

पिन कोड-482002

ई-मेल : edit@haribhoomi.com

वेब-साइट : www.haribhoomi.com

चीन की बाढ़ में टूटा सांपों का फार्महाउस, पानी में तैर रहे हजारों सांप

एजेंसी►► गुआंगशी

चीन इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। इन सबके बीच गुआंगशी इलाके के लोगों को एक अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ रहा है, दरअसल सैकड़ों सांपों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया है। सरकारी ब्रॉडकास्टर के मुताबिक, गुआंगशी में भारी बाढ़ के चलते ब्रीडिंग फार्म से सैकड़ों सांप भाग निकले, जिससे अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहना पड़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स और अन्य चीनी मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 1900 सांप खुले में घूम रहे हैं। बाढ़ से बचने के लिए जुड़ रहे लोगों को सांपों ने डस लिया जिससे अभी तक तीन महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है। खबर है कि गुआंगशी के शहर हेंगझोउ में तीन महिलाओं को सांप के काटने के बाद इलाज नहीं मिल पाया। बाढ़ और रास्तों के बंद होने के कारण वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई थी। सोशल मीडिया पर बाढ़ के पानी में तैरते सांपों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोगों को जोध तक गहरे पानी में उन फुर्तीले सांपों को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।

भागो हुए सांप बेहद खतरनाक प्रजाति के



ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो सांप फार्म से भाग निकले हैं, उनमें कोबरा, करैत, नील और स्पाइडर जैसे जहरीले सांप भी शामिल हैं। भागे हुए सांपों को पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई हैं और अधिकारियों ने सांप के काटने से पीड़ित लोगों के तुरंत इलाज के लिए अस्थायी मेडिकल क्लिनिक भी बनाए हैं।

गुआंगशी में सांप पालने का सबसे बड़ा हब बता दें गुआंगशी चीन में कमर्शियल सांप पालन का सबसे बड़ा हब है, जहां पारंपरिक दवाओं, चमड़े के सामान और मांस के लिए लगभग 3 करोड़ (30 मिलियन) सरीसृपों (रेप्टाइल्स) को पाला जाता है। बुधवार को क्षेत्रीय कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि हेंगझोउ इलाके के कई गांवों के पानी में डूबने के बाद कुछ जगह पानी में सांप देखे गए हैं।

चीन बाढ़ ने बरपा रखा है कहर दरअसल इस इलाके में खतरनाक उफान के बाद जलाशय टूट गए और पानी का तेज बहाव कस्बों और शहरों में घुस गया। इस दौरान छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 1,30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाई गये। गुआंगशी क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय के अनुसार, बचाव अभियान में 8,000 से ज्यादा लोग और लगभग 5,700 नावें तैनात की गई हैं।

टीम के साथ लोग खुद सांप पकड़ने में जुटे



आसपास के ग्रामीणों ने मिलकर एक अपनी टीम बनाई है। यह टीम खुद पानी में घुसकर सांपों को पकड़ रही है। लोगों का कहना है कि अधिकांश सांप पानी में बह गए हैं, लेकिन कुछ कचरे और जमा पानी पर बचे हैं। स्थानीय लोग मछली पकड़ने वाले औजार से सांपों को पकड़ने में जुटे हैं।

खबर संक्षेप

विदेश जाने पर भाजपा ने साधा राहुल पर निशाना

नई दिल्ली। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कथित तौर पर "विदेश में छुट्टियां मनाने" के लिए निशाना साधा और उन्हें एक "अगंभीर राजनेता" बताया जो छात्रों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए करते हैं। सतारूढ़ दल ने दावा किया कि गांधी की गैरमौजूदगी के कारण इस महाने उनके निर्धारित छात्र संवाद कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने गांधी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा राहुल "छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं" और उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के बजाय छुट्टियों को प्राथमिकता दी है।

बताया जो छात्रों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए करते हैं। सतारूढ़ दल ने दावा किया कि गांधी की गैरमौजूदगी के कारण इस महाने उनके निर्धारित छात्र संवाद कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने गांधी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा राहुल "छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं" और उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के बजाय छुट्टियों को प्राथमिकता दी है।

ऋण धोखाधड़ी में बैंक के पूर्व प्रबंधक व नौ कर्मचारी बर्खास्त

थेनी। तमिलनाडु के थेनी जिले में फर्जी महिला स्वयं सहायता समूह के ऋण खातों से जुड़े 14 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी का पता चलने के बाद केनरा बैंक के एक पूर्व शाखा प्रबंधक और नौ अन्य कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोप है कि यह धोखाधड़ी जिले में बैंक की दो शाखाओं में की गई, जहां इस मामले के मुख्य आरोपी कार्तिक शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। शुरुआत में चिन्नामनूर के निकट स्थित ओडार्डपट्टी शाखा में अनधिकृत लेन-देन के माध्यम से 14 करोड़ की अनियमितताओं का पता चला था।

एक करोड़ की सैक बरामद, तस्कर गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 518 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुमित शुक्ला ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच अभियान के दौरान मोटरसाइकिल सवार मुसलीम को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से 518 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी फैमिली कोर्ट के जज से मांगा जवाब दूसरी शादी के बाद पहले पति से गुजारा भत्ता क्यों... ?

एजेंसी►► प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के अतिरिक्त प्रधान जज फैमिली कोर्ट से यह स्पष्ट करने को कहा है कि तलाक के बाद महिला के दूसरी शादी करने की जानकारी होने के बावजूद पहले पति से गुजारा भत्ता देने का आदेश क्यों दिया गया। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट से स्पष्टीकरण तलाब किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह बताएं कि पत्नी के दूसरे विवाह का तथ्य आपति-पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज होने के बावजूद पहले पति से प्रति माह 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश किस आधार पर दिया गया।

खास बातें

- तलाक के लगभग एक महीने बाद महिला ने दूसरा विवाह कर लिया था व शपथ पत्र भी किया था पेष
- इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी

तलाक के बाद महिला ने की दूसरी शादी



मामले के अनुसार पति-पत्नी के बीच 30 जुलाई 2025 को झांसी के अतिरिक्त प्रधान जज फैमिली कोर्ट ने तलाक की डिक्री पारित की थी। पति ने इसके खिलाफ अपील दाखिल की। इस बीच तलाक के लगभग एक महीने बाद महिला ने दूसरा विवाह कर लिया। पति का कहना है कि पत्नी ने शपथपत्र में खुद दूसरी शादी की जानकारी दी थी। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

जबलपुर, शनिवार 11 जुलाई 2026

हरिभूमि

9

यातायात नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश

जबलपुर। जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, डीएफओ पुनीत सोनकर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) अंजना तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार पिछले छह महीनों में जिले में 1903 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 324 लोगों की जान गई, जबकि 2239 लोग घायल हुए। इन आंकड़ों पर गंभीर चिंता जताते हुए कलेक्टर ने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के रूप में तेज रफ्तार, नशे की हालत में वाहन

छह महीने में 1903 सड़क हादसे 324 मौतों पर कलेक्टर सख्त



चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना तथा यातायात संकेतों की अनदेखी को चिन्हित किया गया। कलेक्टर ने यातायात पुलिस को विशेष अभियान चलाकर हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमों का सख्ती से पालन कराने, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ

स्कूल वाहनों पर रहेगा विशेष फोकस.....

बैठक में शहर के भीतरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाने, अर्द्ध पार्किंग पर नियंत्रण और ई-रिवशा संचालन को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया। जयंती टॉकीज और बल्देवबाग जैसे व्यस्त क्षेत्रों में विशेष यातायात प्रबंधन लागू करने के निर्देश भी दिए गए। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने स्कूल वाहनों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन तैयार करने, सभी वाहन चालकों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराने तथा स्कूल संचालकों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नो-एंट्री क्षेत्रों में कैमरे लगाने, सभी विन्डिड ब्लैक स्पॉट्स को समाप्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने तथा बारिश के दौरान सड़कों पर आने वाले गीवेंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।



आर्मी पब्लिक स्कूल क्रमांक-2 में ‘हैक फेस्ट-2026’, नवाचार में जबलपुर टीम बनी चैंपियन

जबलपुर। मुख्यालय मध्य भारत एरिया के तत्वावधान में आर्मी पब्लिक स्कूल क्रमांक-2, जम्मू एवं कश्मीर राइफलस रेजिमेंटल सेंटर द्वारा बत्रा ऑडिटोरियम में ‘हैक फेस्ट-2026’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्रिगेडियर उदय साम्वाल, क्रमांडेंट ने किया। इस अवसर पर श्रीमती रेनु साम्वाल, अध्यक्ष, फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।प्रतियोगिता में प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी तथा जबलपुर के आर्मी पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने तकनीकी मॉडल एवं नवाचार परियोजनाएं प्रस्तुत कीं। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मध्य भारत एरिया ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच और तकनीकी कौशल की सराहना की। प्रतियोगिता में आर्मी पब्लिक स्कूल क्रमांक-2, जबलपुर ने प्रथम स्थान और समग्र चैंपियनशिप हासिल की, जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या दूसरे तथा आर्मी पब्लिक स्कूल प्रयागराज तीसरे स्थान पर रहे। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया।



जेडीओएस का छठा वार्षिक सम्मेलन कल, देशभर के नेत्र रोग विशेषज्ञ जुटेंगे

जबलपुर। डिवायजनल ऑर्थोल्मिक सोसायटी (जेडीओएस) द्वारा प्रो. डॉ. आर.के. मिश्रा मेमोरियल के छठे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 12 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे वेलकम होटल बाय आईटीसी, जबलपुर में होगा। सम्मेलन में देशभर के प्रतिष्ठित नेत्र रोग विशेषज्ञ ऑक्युलोप्लास्टी, ऑर्बिट, नेत्र आघात एवं आधुनिक नेत्र चिकित्सा से जुड़े नवीनतम विषयों पर अपने शोध और अनुभव साझा करेंगे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि विवेक रुसिया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि प्रो. डॉ. नवनीत सक्सेना, डीन, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज रहेंगे। मुख्य वक्ता पद्मश्री डॉ. अशोक कुमार प्रोवर (नई दिल्ली) तथा डॉ. नरेन्द्र पाटीदार (जानकीकुंड, चित्रकूट) विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे। सम्मेलन में वैज्ञानिक सत्र, केस प्रेजेंटेशन, प्रो. डॉ. आर.के. मिश्रा मेमोरियल अवार्ड सत्र एवं युवा नेत्र रोग विशेषज्ञों के लिए वैज्ञानिक प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। जेडीओएस के अध्यक्ष डॉ. रविन दास ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सकों को आधुनिक उपचार पद्धतियों से अवगत कराना है। वहीं, सचिव डॉ. अविजित विश्वा ने नेत्र रोग विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षणरत चिकित्सकों से अधिकाधिक संख्या में सहभागिता की अपील की।



राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में जबलपुर के चार विशेष खिलाड़ी करेंगे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व

जबलपुर। देहरादून में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश की चार सदस्यीय विशेष टीम में जबलपुर के ईशान गुप्ता, उत्कर्ष कुमार जैन, श्रेष्ठ मिश्रा और राघव वर्मा का चयन हुआ है। सभी खिलाड़ी विशेष ओलंपिक भारत (मध्य प्रदेश) की ओर से राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।खिलाड़ियों ने मुख्य कोच रामकिशोर सोनी एवं असिस्टेंट स्पोर्ट्स कोच अमर कदम के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। वेलकम टू स्पेशल चाइल्ड स्पोर्ट्स अकादमी, जबलपुर की संरक्षिका डॉ. मधुलिका त्रिपाठी और ज्योत्सना सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। वहीं, विशेष ओलंपिक भारत (मध्य प्रदेश) के क्षेत्रीय निदेशक दीपांकर बेनर्जी, खेल निदेशक एहतेशाम उद्दीन तथा सहायक खेल निदेशक राजेंद्र बारस्कर ने टीम को बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन और पदक जीतने की शुभकामनाएं दीं। चयन से शहर में हर्ष का माहौल है।

विद्युत अग्नि सुरक्षा दिवस पर हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन, ‘जीरो एक्सीडेंट’ लक्ष्य पर दिया जोर

जबलपुर। राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा दिवस-2026 के अवसर पर नई दिल्ली स्थित मानकशां सेंटर के जोरावर ऑडिटोरियम में विद्युत अग्नि सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में विद्युत जनित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुरक्षित कार्य संस्कृति और जन-जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। भारत सरकार के विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने अपने संदेश में कहा कि विद्युत अवसंरचना के विस्तार के साथ सुरक्षा और जिम्मेदारी की संस्कृति को मजबूत करना आवश्यक है। वहीं विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद यैसो नाइक ने नागरिकों से घरों और कार्यस्थलों को विद्युत दुर्घटनाओं से सुरक्षित बनाने की अपील की। सम्मेलन में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के



अध्यक्ष एवं पदेन सचिव घनश्याम प्रसाद, विद्युत प्रणाली सदस्य एवं पदेन अपर सचिव विजय कुमार सिंह तथा बीएसईएस के निदेशक अमल सिन्हा ने विद्युत सुरक्षा पर विचार रखे। विशेषज्ञों ने विद्युत सुरक्षा को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने, नियमित जांच, सुरक्षित वायरिंग, विशेषज्ञों की सलाह और “जीरो एक्सीडेंट” लक्ष्य को प्राथमिकता देने के सुझाव दिए। सम्मेलन में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व ऊर्जा विभाग की ओर से मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सहायक अभियंता (सतर्कता) एवं जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत ओझा ने किया। विशेषज्ञों ने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में सुरक्षित एवं जिम्मेदार विद्युत उपयोग की अहम भूमिका होगी।

“हर-हर महादेव” जयघोष के बीच संपन्न हुआ शिव-पार्वती विवाह, गुरुधाम ग्वारीघाट में उमड़ा आस्था का सैलाब

शिवमहापुराण कथा के चौथे दिन हुआ दिव्य विवाहोत्सव मजनों और वैदिक मंत्रोच्चार से भक्त हुए भाव-विभोर

जबलपुर। माँ नर्मदा के पावन तट स्थित गुरुधाम, ग्वारीघाट में आयोजित आठ दिवसीय श्री शिवमहापुराण कथा के चौथे दिन बुधवार को भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाहोत्सव श्रद्धा, उल्लास और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार, मंगल गीतों और 'हर-हर महादेव' के गगनभेदी जयघोष से पूरा कथा परिसर



भक्तिमय हो उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव-पार्वती विवाह के साक्षी बनकर स्वर्ग को धन्य माना। कथा व्यास पूज्य आशीर्वाद महाराज (श्रीधाम वृंदावन) ने शिव-पार्वती विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि यह विवाह केवल दो दिव्य शक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के सनातन स्वरूप की एकता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि

भगवान शिव वैराग्य, तप और कल्याण के प्रतीक हैं, जबकि माता पार्वती शक्ति, समर्पण और सृजन की अधिष्ठात्री हैं। दोनों का मिलन संसार में धर्म, संतुलन और मंगल की स्थापना का संदेश देता है। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने शिव-पार्वती विवाह की झांकी का दर्शन कर पुष्पवर्षा की और भक्ति रस में सराबोर होकर भजनों पर नृत्य किया। पूरा गुरुधाम परिसर भगवान

भोलेनाथ की भक्ति में डूबा नजर आया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पुरुषों ने डमरू की थाप पर 'बम-बम भोले' के नारे लगाए।

नित्य हो रहे हैं अनुष्ठान

आयोजन के अंतर्गत प्रतिदिन प्रातः 7 से 8:30 बजे तक शिवलिंग निर्माण, सुबह 9 से 11 बजे तक रुद्राभिषेक तथा दोपहर 3 से शाम 6:30 बजे तक श्री शिवमहापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का समापन 12 जुलाई को हवन, पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे के साथ होगा। कथा का सीधा प्रसारण श्री राधाकृष्ण राधा यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है। आयोजक नेमा परिवार ने श्रद्धालुओं से कथा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने का आग्रह किया है।

डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड में किया गया 1 करोड़ के 14 विकास कार्यों का भूमिपूजन

विधायक लखन घनघोरिया ने रखी आधारशिला



जबलपुर। नगर निगम के डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड क्रमांक-40 में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत 14 विकास कार्यों का भूमिपूजन पूर्व मंत्री एवं पूर्व क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने गोहलपुर स्थित अंसारी भवन के समीप आयोजित समारोह में किया। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, पेयजल सहित मूलभूत सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है और वार्ड के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस

नेता कदीर सोनी, अब्दुल हकीम बाबा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा, पार्षद अखतर अंसारी, गुलाम हुसैन, वकील अंसारी, कलीम खान, कांग्रेस

स्थापना, कांटा बोड़ी मैदान के सौंदर्यीकरण तथा मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान में टीन शेड सहित कुल 14 विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई।वार्ड पार्षद मुकीमा याकूब अंसारी ने कहा कि इन कार्यों से वार्डवासियों को आवागमन, जल निकासी और पेयजल जैसी सुविधाओं में राहत मिलेगी। अंत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता याकूब अंसारी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद ताहिर अली सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी में 139 सहायक अभियंता बने कार्यपालन अभियंता, 1,944 को मिला पदोन्नति का लाभ

जबलपुर। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने पदोन्नति प्रक्रिया के तहत 139 सहायक अभियंताओं को कार्यपालन अभियंता (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) के पद पर पदोन्नत किया है। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों के लिए इसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। कंपनी के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर अब तक विभिन्न संवर्गों के कुल 1,944 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है।इन्हें प्रथम श्रेणी के 78, द्वितीय श्रेणी के 147, तृतीय श्रेणी के 627 तथा चतुर्थ श्रेणी के 1,092 कर्मचारी शामिल हैं। प्रबंध संचालक अजय गुप्ता एवं मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) सम्पद सराफ गुजर ने सभी पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पदोन्नति नई जिम्मेदारियों के साथ बेहतर कार्यकुशलता और गुणवत्तापूर्ण विद्युत सेवाएं देने का अवसर भी है।

CHANGE OF NAME
I, SUNITA SIDDHARTH INGLE Mother of 4591837M Rank NK Name INGLE AJAY SIDDHARTH presently, residing at VILL-MARODA, PO-KAWASA, TEH-AKOT, DISTT-AKOLA (MAHARASHTRA)- 444101 I, have changed of my name from SUNITA A S INGLE (Name as per my son, Army service records) to SUNITA SIDDHARTH INGLE (name as per my AADHAR CARD NO. 9010 5471 5208) vide affidavit dated 10/07/2026 formerly before Public Notary JABALPUR (MP)
CORRECT NAME
SUNITA SIDDHARTH INGLE
INCORRECT NAME
SUNITA A S INGLE

CHANGE OF NAME AND DATE OF BIRTH
I, ARMY NO. 15229013W RANK LINK NAME NYAS C P S/O ABDU RAZAK CP OF UNIT COA (W), GCF, JABALPUR (MP) AADHAR CARD No. 7009 4173 72221, have changed name and date of birth of my FATHER from name ABDU RAZAK C P and date of birth 28/01/1964 (Name and date of birth as per my FATHER, AADHAR CARD NO. 9246 1054 1243) vide affidavit dated 09/07/2026 (date of affidavit) formerly before Public Notary RAMDAS SHARMA MP HIGH COURT, JABALPUR (Name and place of Court).
CORRECT NAME
ABDUL RAZAK C P
CORRECT DATE OF BIRTH
28/01/1962
INCORRECT NAME - ABDU RAZAK CP
INCORRECT DATE OF BIRTH
28/05/1964

CHANGE OF NAME
I, ARMY NO. 15229013W RANK LINK NAME NYAS C P S/O ABDU RAZAK CP OF UNIT COA (W), GCF, JABALPUR (MP) AADHAR CARD No. 7009 4173 72221, have changed name of my MOTHER from name BASHEERA (Name as per my Army Service Records) to BASHEERA C V (Name as per my MOTHER AADHAR CARD NO. 6120 4897 3616) vide affidavit dated 09/07/2026 (date of affidavit) formerly before Public Notary RAMDAS SHARMA MP HIGH COURT, JABALPUR (Name and place of Court).
CORRECT NAME
BASHEERA CV
INCORRECT NAME
BASHEERA

CHANGE OF NAME
I, SIDDHARTH BALIRAM INGLE Father of 4591837M Rank NK Name INGLE AJAY SIDDHARTH presently, residing at VILL -MARODA, PO-KAWASA, TEH-AKOT, DISTT- AKOLA (MAHARASHTRA)- 444101 I, have changed of my name from SIDDHARTH BALIRAM INGLE (Name as per my son, Army service records) to SIDDHARTH BALIRAM INGLE (name as per my AADHAR CARD NO. 3640 9220 9181) vide affidavit dated 10/07/2026 formerly before Public Notary JABALPUR (MP)
CORRECT NAME
SIDDHARTH BALIRAM INGLE
INCORRECT NAME
SIDDHARTH BALIRAM INGLE



खबर संक्षेप

28,372 मीट्रिक टन पहुंची राठी स्टील की बिक्री

नई दिल्ली। स्टेनलेस स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और टोएमटी बार्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में शामिल राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 30 जून 2026 को समाप्त पहली तिमाहीके लिए मजबूत परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी ने बिक्री मात्रा और कारोबार में वृद्धि हासिल की। वित्तवर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री मात्रा 28,372 मीट्रिक टन रही। कंपनी के स्टेनलेस स्टील उत्पादों और एमएस टोएमटी रीबार के विविध उत्पाद पोर्टफोलियो तथा बाजार विस्तार की रणनीति के कारण संभव हुआ।

सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल का प्री-रिजर्वेशन शुरू

गुन्गुग्राम। सैमसंग ने भारत में अपनी अगली गैलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन सीरीज के लिए प्री-रिजर्वेशन शुरू करने की घोषणा की है। ग्राहक इन नए फोल्डेबल डिवाइसों को ग्लोबल लॉन्च से पहले प्री-रिजर्व कर सकते हैं। ग्राहक 999 रुपए की रिफंडेबल टोकन राशि देकर आगामी गैलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का प्री-रिजर्वेशन कर सकते हैं। यह सुविधा सैमसंगडॉटकॉम, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स, अमेजनडॉटइन,फ्लिपकार्टडॉटकॉम और देसीभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है।

फिलपकार्ट की फूड एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी में 50% की वृद्धि, टियर-2 शहरों से बड़ी मांग

नई दिल्ली। घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फिलपकार्ट ने अपनी फूड एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी में सालाना आधार पर 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के अनुसार इस बढ़ोतरी में जैन-जी ग्राहकों, टियर-2 और टियर-3 शहरों के उपभोक्ताओं तथा फिलपकार्ट मिनट्स की अहम भूमिका रही है, जिसकी कुल मांग में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।फिलपकार्ट के वाइस प्रेसिडेंट (कंज्यूमेबल्स) निशांत दलाल ने कहा कि उपभोक्ता अब स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रोटीन ओट्स, प्रोटीन मूसली, हाई-प्रोटीन पीट बटर, ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, कोल्ड-प्रेसड ऑयल और प्रीमियम हेल्थ फूड की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी ने बताया कि पिछले एक वर्ष में इन उत्पादों की ऑनलाइन खोज में 80 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। कंपनी के तीसरे फिलपकार्ट फूड फेस्ट 2026 में 50 से अधिक ब्रांड, 1,000 से ज्यादा क्रिएटर्स और कई सेलिब्रिटी शेफ शामिल हुए। आयोजन में 10 से अधिक नए उत्पाद लॉन्च किए गए, जबकि 7 से 15 जुलाई तक ग्राहकों के लिए विशेष इन-ऐप ऑफर्स भी उपलब्ध कराए गए।

राशिफल

	मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कारदि कार्यों में सफलता मिलेगी। सन्तान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
	आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में सुधार होगा, परन्तु परिश्रम अधिक रहेगा।आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति रहेगी।
	आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। धर्म के प्रति श्रद्धाभाव रहेगा। वरुणों पर खर्च बढ़ सकते हैं। मन अशान्त रहेगा।
	परिश्रम अधिक रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। कुटुम्ब-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भाइयों के सहयोग से कारोबार को गति मिल सकती है।
	वर्ष के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचे वरुणों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं। आय की स्थिति में सुधार होगा। सेहत का ध्यान रखें। सन्तान सुख में वृद्धि होगी।
	क्रोध एवं आदेश के अतिरेक से बचें। परिवार में शान्ति एवं सद्भाव बनाये रखने के लिए प्रयास करें। नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होगी।
	स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। सम्पत्ति में वृद्धि होगी।
	कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। मानसिक शान्ति बनाये रखें। माता का सान्निध्य मिलेगा। धर्म के प्रति श्रद्धाभाव रहेगा।
	मित्रों के साथ धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। घर-परिवार में धार्मिक-मंगलिक कार्य होंगे। भवन की साज-सज्जा पर खर्च अधिक रहेगा।
	आलस्य में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा, लेकिन परिणाम सन्दिग्ध हैं। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं।
	खर्च बढ़ेंगे। आय के साधन बन सकते हैं। नौकरी में इच्छा-विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम की अधिकता रहेगी।
	कारोबार में सुधार के लिए भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। रहन-सहन कष्टदायी होगा। तनाव से बचें।

एमडी कुमार पुरुषोत्तम ने मिशन मोड पर डीपीसी के दिए निर्देश

वाणिज्य प्रतिनिधि ►►भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन (मंडी) बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारियों को करीब 16 वर्ष बाद पदोन्नति की सौगात मिली है। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की अनुशंसा पर मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक एवं आयुक्त कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर पहले चरण में करीब 50 अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, मंडी बोर्ड मुख्यालय के चक्कर लगाए बिना ही अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला, जिससे विभाग में खुशी का माहौल है। इससे पहले वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रबंध संचालक एवं आयुक्त अजातशत्रु श्रीवास्तव के कार्यकाल में बड़े स्तर पर पदोन्नतियां हुई थीं।



कुमार पुरुषोत्तम का आभार व्यक्त करते योगेश नागले

विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति आदेश जारी

मंडी बोर्ड अधिकारियों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के बाद मंडी बोर्ड के एमडी कुमार पुरुषोत्तम ने मिशन मोड में डीपीसी की प्रक्रिया पूरी कराते हुए लंबित मामलों का निराकरण कराया। इसके बाद विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति आदेश जारी किए गए। बताया जा रहा है कि पहले चरण में संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, अनुभाग अधिकारी, सचिव-अ तथा अन्य पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं।

अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को मिलेगा नया आयाम

वीआईटी यूनिवर्सिटी में एनएआरएल ने स्थापित किया जीएनएसएस रिसीवर

हरिभूमि न्यूज ►►भोपाल

वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) ने विश्वविद्यालय परिसर में जीएनएसएस (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) रिसीवर प्रणाली स्थापित की है। यह स्थापना एनएआरएल की "नॉर्थ-साउथ चैन फॉर आयनोस्फीयर एंड स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन" परियोजना के तहत की गई है।



ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम

विश्वविद्यालय अनुसंधान ढांचे को और मजबूत करेगी

विश्वविद्यालय के अनुसार, यह अत्याधुनिक प्रणाली आयनोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम (स्पेस वेदर) के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराएगी। इससे अंतरिक्ष विज्ञान, स्वदेशी नेविगेशन तकनीक और भू-स्थानिक अनुसंधान को नई गति मिलेगी। यह जीएनएसएस रिसीवर टोटल इलेक्ट्रॉन कंटेन, आयनोस्फेरिक सिटिलेशन, सिग्नल क्षरण, लॉस ऑफ लॉक तथा सौर और भू-चुंबकीय गतिविधियों से उत्पन्न आयनोस्फेरिक बदलावों को निरंतर निगरानी करेगा। इससे प्राप्त आंकड़े अंतरिक्ष मौसम, भूगणित, उपग्रह नेविगेशन और पोजिशनिंग-नेविगेशन-टाइमिंग से जुड़े शोध कार्यों में उपयोगी साबित होंगे।



खुले नाले में गिरा व्यापारी का स्कूटर, घायल हो रहे राहगीर



नाले में गिरे स्कूटर को निकलते हुए

में नाला लंबे समय से खुला पड़ा है। इसकी शिकायत कई बार नगर निगम से की जा चुकी है, लेकिन अब तक

नाले को ढकने या सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। व्यापारी अनुपम अग्रवाल के अनुसार, यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी खुले नाले के कारण कई लोग हादसे का शिकार होकर घायल हो चुके हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। व्यापारियों ने नगर निगम से मांग की है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खुले नाले को तत्काल ढका जाए और बाजार क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

स्वराज ने मग्न में लॉन्च किया नया 855 प्रोटेक ट्रैक्टर

मुंबई/भोपाल। महिंद्रा समूह की कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स ने मध्य प्रदेश में अपना नया स्वराज 855 प्रोटेक ट्रैक्टर लॉन्च किया है। 2WD और 4WD विकल्पों में उपलब्ध यह ट्रैक्टर आधुनिक तकनीक, मददार प्रदर्शन और स्मार्ट फीचर्स से लैस है, जिससे किसानों को अधिक उत्पादकता, बेहतर दक्षता और आरामदायक संचालन मिलेगा।कंपनी के अनुसार ट्रैक्टर में 12 फॉरवर्ड व 3 रिवर्स गियर, 2,500 किलोग्राम लिफ्टिंग क्षमता, स्मार्ट कनेक्ट टेलीमेटिक्स सिस्टम, 70 लीटर प्यूल् टैंक और 500 घंटे का सर्विस इंटरवल जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसमें रियल-टाइम लोकेशन, ईंधन की जानकारी, सर्विस अलर्ट और सुरक्षा संबंधी स्मार्ट फीचर्स भी उपलब्ध हैं। स्वराज डिवीजन के सीईओ गगनजोत सिंह ने कहा कि प्रोटेक किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख कृषि राज्य के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा।



20 टीमों ने नवाचार, गुणवत्ता एवं समस्या समाधान के उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत किए

सीआईआई मग्न की 37वीं क्वालिटी सर्कल प्रतियोगिता संपन्न

वाणिज्य प्रतिनिधि ►►भोपाल

भारतीय उद्योग परिसंच (सीआईआई) मध्यप्रदेश द्वारा भोपाल में 37वीं क्वालिटी सर्कल प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 11 प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों की 20 टीमों ने भाग लिया और अपने-अपने उद्योगों में अपनाई गई गुणवत्ता सुधार, नवाचार एवं समस्या समाधान से जुड़े सफल प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। यह प्रतियोगिता कर्मचारियों को अपने अनुभव साझा करने, एक-दूसरे से सीखने तथा उद्योगों में गुणवत्ता आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने



नवाचारों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाला राष्ट्रीय मंच

का एक प्रभावी मंच साबित हुई। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से आई टीमों ने अपने नवाचार, कार्यप्रणाली और सभ्यता प्रथाओं को प्रस्तुत कर निरंतर सुधार की भावना को मजबूत किया। प्रतियोगिता में विशेषज्ञ निर्णायक मंडल द्वारा प्रस्तुतियों एवं प्रश्नोत्तर के आधार पर विजेताओं की घोषणा की गई। इस अवसर पर सी.पी. शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई मध्यप्रदेश एवं प्रबंध

निदेशक, दौलतराम इंजीनियरिंग ने कहा कि नवाचार केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को 37 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की मजबूत नींव है। सीआईआई पदाधिकारियों ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी टीमों को बधाई दी। जिससे उन्हें अपने नवाचारों एवं उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

RAMP योजना के तहत मंडला में दो दिवसीय MSME जागरूकता कार्यशाला संपन्न

मंडला। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की RAMP योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (MPLUN) ने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (DTIC) के सहयोग से मंडला में दो दिवसीय कॉम्पोजिट MSME जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में MSME उद्योगियों, स्टार्टअप्स, व्यापारियों, युवाओं एवं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को उद्यम स्थापना, व्यवसाय विस्तार, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन तथा सरकारी योजनाओं की विस्तृत

जानकारी दी गई। कार्यक्रम में दिनेश कुमार मररकोले, अनिल विरानी, सुरेंद्र पमनानी एवं उद्योगपति गिरीश जी ने स्थानीय उद्यमिता को रोजगार और आर्थिक विकास का आधार बताते हुए युवाओं को शासन की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं विशेषज्ञ मयूर कुमार शर्मा, हिरेन्द्र ठाकुर, हेमंत झा, सुधा एवं चंदन बाधवानी ने ONDC, ZED, IPR, GI, SHG Formalization, वित्तीय सशक्तिकरण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यवसाय विस्तार पर मार्गदर्शन दिया।

पदोन्नत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उच्च पद का कार्यभार ग्रहण के दिए निर्देश

सभी पदोन्नतियां सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) क्रमांक 13954/2016 तथा भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेशों के अधीन है। सभी पदोन्नत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वर्तमान पद से कार्यमुक्त कर उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत वेतन निर्धारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश प्राप्त के एक माह के भीतर अपना विवरण प्रस्तुत करना होगा।

कुमार पुरुषोत्तम प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड

खाद्य विश्लेषक कर न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी जांच रिपोर्ट में देरी,मिलावट के मामलों में एक्शन पर असर, बच रहे मिलावटखोर

वाणिज्य प्रतिनिधि ►►भोपाल

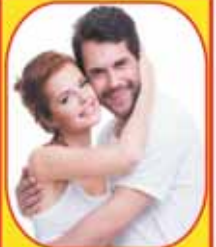
मध्यप्रदेश के खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। खाद्य विश्लेषकों पर आरोप है कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को नहीं भेज रहे हैं और अगर रिपोर्ट भेज दी भी जाती है संबंधित अधिकारी रिपोर्ट को अमल लाते हुए कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं जिससे मिलावट के मामलों में कार्रवाई प्रभावित हो रही है। विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिनियम के तहत खाद्य विश्लेषक को सामान्यतः 14 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट भेजनी होती है। यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं हो, तो उसे देरी का कारण बताते हुए संबंधित डेजिनेटेड अधिकारी

को लिखित सूचना देनी होती है। लेकिन कई मामलों में न तो समय पर रिपोर्ट भेजी जा रही है और न ही देरी का कारण बताया जा रहा है। हाल ही में एक मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान भी जांच रिपोर्ट में हुई देरी का मुद्दा उठा। इस मामले के बाद खाद्य विश्लेषकों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर सवाल और तेज हो गए हैं। विभागीय सूत्रों का दावा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी समय पर नमूने लेकर उन्हें प्रयोगशाला तक पहुंचा देते हैं। प्रयोगशाला में प्रारंभिक जांच भी समय पर पूरी हो जाती है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट संबंधित जिलों को भेजने में कई बार सप्ताहों या महीनों की देरी हो जाती है। इससे मैदानी अमले को कार्रवाई कमजोर पड़ने और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है।

रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का ऑडिट कराया जाए

खाद्य विभाग अधिकारियों का कहना है कि यदि रिपोर्ट में अनावश्यक देरी होती है, तो इसका लाभ आरोपित व्यापारियों को मिलता है और मिलावट के मामलों में अभियोजन कमजोर पड़ सकता है। विभागीय सूत्रों ने कहाकि रिपोर्ट भेजने में देरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अतः इसकी उच्चस्तरीय जांच कर यह तय किया जाना चाहिए कि देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया है कि खाद्य प्रयोगशालाओं में रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का ऑडिट कराया जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

छोटा लिंग निराश क्यों? जोश जगा दे धूम मचा दे।



18 से 80 वर्ष तक लाभदायक लिंगको 8-9 इंच लम्बा मोटा, कठोर बनाये। सेक्स दाइज 30 से 45 मिनट बड़ाए। क्यों की कमजोरी बामदी,धातु का पतलापन,शुक्र,बी.पी. में भी लवरदरत लाभदायक। घर बैठे मंगवाये। लाभ नही तो पैसे वापिस। 09083218330

सूचना - पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार पत्र में पड़ोसित सभी पड़ार के विद्यापन। (इसमें एवं रनिंग बत्तासीआईड में दिश गए तथ्यों के बारे में अपने रिपोर्ट सं निर्माण तें। हरिभूमि समूह की विद्यापनो के तथ्यों से संबंधित कोई भिन्नदारी नही होगी।

सूडोकु नवताल - 6293										***** ठडिनाल									
	9							6						2					
	1													3					
5						7												6	
							4							9					
4											8								
	7										9							8	
		2													1				
									3								4		
■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक परे जाने आवश्यक हैं.										सूडोकु नवताल - 6292 का हल									
■ प्रत्येक आठो और खडो पंक्ति में एवं 3×3 के बर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.										6	5	8	9	1	4	2	7	3	
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.										1	2	7	3	5	8	6	4	9	
■ पहली का केवल एक ही हल है.										3	4	9	7	2	6	1	5	8	
										2	3	6	1	4	5	9	8	7	
										8	9	5	2	7	3	4	1	6	
										4	7	1	6	8	9	3	2	5	
										7	6	4	5	3	1	8	9	2	
										9	8	2	4	6	7	5	3	1	
										5	1	3	8	9	2	7	6	4	

MANUAL SENAGHA, BANGALORE

इंग्लैंड के कप्तान ने कहा, 'ईमानदार से कहूँ तो भारत जैसे टीम को 4-0 से हराना बेहद विशेष उपलब्धि होगी और इसके साथ दुनिया की शीर्ष रैंकिंग का टीम बनना इसे और भी यादगार बना देगा।' इंग्लैंड के कप्तान ने मनाफा कि उन्हें भारत के खिलाफ इतनी आसान सफलता की उम्मीद नहीं थी। ब्रुक ने कहा, हमारी सीमित ओवरों की टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने लगातार बेहतर क्रिकेट खेली है और विभिन्न परिस्थितियों तथा पिचों के अनुसार खुद को अच्छे तरह ढाला है। विश्व कप में भी हमारा प्रदर्शन शानदार रहा था।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की पहली टीम है जो पहला मैच होगा जब बिग बैश लीग का कोई मैच विदेशी धरती पर खेला जाएगा। हालाँकि, युवाओं की वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआर) कई बार ऑस्ट्रेलिया का आयोजन घर से बाहर कर चुका है। अगर वे इस पहली बार होगा जब किसी विदेशी टी20 लीग का मैच भारत में होगा। इसकी वजह यह भी है कि भारत में क्रिकेट की काफी महत्व दिया जाता है। देश में क्रिकेट को लेकर खास तरह का जुनून भी देखने को मिलता है। भारत में क्रिकेट का बाजार भी काफी बड़ा है और स्टैंडिंग्स में लाखों की संख्या में फैंस पहुँचते हैं।

हाईकोर्ट का अनोखा सुधारात्मक आदेश, गलियारों में जोरदार चर्चा

खारिज केस बहाल कराना है तो वकील को दृष्टि श्रवण बाधित स्कूल में कम्प्युनिटी सर्विस देनी होगी

जबलपुर। वकील साहब गायब, तो केस खारिज! – अदालतों में अक्सर दिखने वाली इस लापरवाही पर मप्र हाईकोर्ट ने जोरदार ऐसा चाबुक चलाया है। लीगल कॉरिडोर में इसकी चर्चा थम नहीं रही है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वकीलों की 'लेट-लतीफी' या लापरवाही का खामियाजा उन गरीब और मजबूर मुर्बकिलों को नहीं भुगतना पड़ेगा, जो न्याय की आस में अपनी चप्पलें घिस देते हैं।

इसी सोच के साथ, जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बी.पी. शर्मा की डिवीजन बेंच ने एक खारिज याचिका को बहाल करने के लिए जेब से जुर्राना भरने के बजाय, दिल से 'कम्प्युनिटी सर्विस' करने का अनोखा और ऐतिहासिक आदेश सुनाया है। बेंच ने केस के वकील को कम्प्युनिटी सर्विस करने पर ही फिर से याचिका बहाल करने को कहा है। इसे समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की संवेदनशीलता जगाने वाला एक टेस्ट केस करार दिया है।

मामला एक मिसिलेनियस पिटीशन (विविध याचिका) का था, जो वकील के न आने के कारण खारिज हो गई थी। जब



वकील इसे दोबारा बहाल कराने पहुंचे, तो कोर्ट ने उनके सामने एक 'स्पेशल टास्क' रख दिया। कोर्ट ने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के वकील को जबलपुर के अंधमूक बायपास स्थित शासकीय दृष्टि व श्रवण बाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाना होगा। वकील को ₹2,500 मूल्य के बढ़िया खाद्य पदार्थ और स्नेक्स लेकर वहां पहुंचना होगा। इन स्पेशल बच्चों के साथ कम से कम एक घंटा बिताना होगा, उनसे बातें करनी होंगी।

ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट व जिला अधिवक्ता संघ में भारसाधक समिति नियुक्ति और एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर में वरिष्ठ (भारसाधक) समिति नियुक्त कर दोनों बार संघों के एक साथ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी स्टेट बार काउंसिल को एडवांस नोटिस जारी किया है। जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने स्टेट बार को दो दिन के भीतर निर्देश लेकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई, 2026 को निर्धारित की गई है। कोर्ट के

अमानक गुटखा बेचने पर छह माह की जेल, 10 हजार का जुर्माना

जबलपुर। अमानक और मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित गुटखा बेचने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी शमशेर हुसैन को दोषी पाया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59(1) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरुण कुमार गोयल की कोर्ट ने उसे छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार 26 सितंबर, 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधुरी मिश्रा ने इन्कम टैक्स आफिस के सामने स्थित आरोपी के मुन्ना पान भंडार का औचक निरीक्षण किया था। जांच

के दौरान गुटखा के 50 पैकेट विधिवत नमूने के रूप में लेकर उन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया। जांच रिपोर्ट में नमूना असुरक्षित पाया गया। इसके बाद अभियोजन स्वीकृति लेकर न्यायालय में परिव्राद प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवत उईके ने पैरवी की। उनके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराकर सजा सुनाई। इस मामले में उप संचालक (अभियोजन) केएस मुवेल और सहायक निदेशक हनुमंत किशोर शर्मा का मार्गदर्शन रहा।



रेलवे स्टेशन पर 100 पाव अवैध शराब जब्त, युवक गिरफ्तार

जबलपुर। जी.आर.पी. जबलपुर ने रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को 100 पाव अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। कारवाई प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 के इटारसी छोर पर की गई, जहां संधिध युवक रेलवे ट्रैक पार कर झोला लेकर जा रहा था। पकड़े गए आरोपी को पहचान मानतलैया निवासी 24 वर्षीय आरुष उर्फ अंशुल चौटेल के रूप में हुई है। तलाशी में उसके पास से 18 लीटर देशी मसाला मद्धि बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 10 हजार 700 रुपए बताई गई है। आरोपी शराब रखने संबंधी कोई वद्द दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जी.आर.पी. ने शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबाकरी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

हवाई फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने एक महीने से फंशर चल रहे हवाई फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गोरखपुर सीएसपी महादेव नागोतिया ने बताया है कि 8 जून 2026 की रात संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की चंदन कॉलोनी में कार में कटु मारने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। शिकायत के अनुसार विवाद बढ़ने पर आरोपी इंगेथ रजक अपने घर से पिस्टल लेकर आया और लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग कर दी और लेकिन आरोपी मौके से फंशर हो गया था। आखिरकार लम्बी तलाश के बाद आरोपी पुलिस के हाथ लग गया।

हरिभूमि कम्प्यूनिक्शंस प्राइवेट लिमिटेड से लिए मुद्रक एवं प्रकाशक अचित महेश्वरी द्वारा हरिभूमि प्रेस, 66/1, इंडस्ट्रीयल एरिया, रिछाई, जबलपुर (मध्यप्रदेश) – 482002 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, 66/1, इंडस्ट्रीयल एरिया, रिछाई, जबलपुर (मध्यप्रदेश) – 482002 से प्रकाशित। प्रधान संपादक-डॉ. हिमांशु द्विवेदी RNI No.: MPHIN/2008/24240

ये किसी छोटे ईश्वर की संतान नहीं

कोर्ट ने अपने आदेश में दिल छू लेने वाली टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कम्प्युनिटी सर्विस कोई कानूनी खानपूर्ति नहीं है। यह एक घंटा वकीलों को आत्मिक संतुष्टि तो देगा ही, साथ ही इन बच्चों को भी यह मरोसा दिलाएगा कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। उन्हें कभी यह अहसास नहीं होना चाहिए कि वे किसी छोटे ईश्वर की संतान हैं।

सोशल ऑडिट' का नया फॉर्मूला

इस फैसले के जरिए हाईकोर्ट ने एक बड़े सिजन 'सोशल ऑडिट' (सामाजिक निगरानी) की नींव भी रख दी है। कोर्ट ने चिंता जताई कि अनाथालयों, दूकानाश्रमों और शेल्टर होम्स से अक्सर दुर्व्यवहार या गड़बड़ियों की खबरें आती हैं।हाईकोर्ट ने कहा कि अगर समाज के संभांत और पढ़े-लिखे लोग जैसे डॉक्टर, वकील, सीए और बड़े सरकारी अफसर इन सरकारी संस्थाओं का नियमित दौरा करना शुरू कर दें, तो एक सोशल प्रेशर बनेगा। जब बड़े अफसर या वकील अचानक आते-जाते रहेंगे, तो किसी भी मैनेजर या कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह बच्चों या बुजुर्गों के साथ बदसलूकी कर सके।

बिना एफिडेविट नहीं खुलेगी फाइल

अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वकील इस आदेश को हल्के में न लें। स्कूल से लौटने के बाद वकील को वहां के हालात, अपने अनुभव और सुधार के सुझावों की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी होगी। इस रिपोर्ट को एक शपथ पत्र के साथ कोर्ट में जमा करना होगा। जब यह अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ जाएगी, केवल तभी संबंधित याचिका को दोबारा सुनवाई के लिए बहाल किया जाएगा।

सरकार को भी टास्क: मुख्य सचिव को मेजी गई कॉपी

मामला सिर्फ एक वकील की सजा तक सीमित नहीं है। हाईकोर्ट ने इस आदेश की कॉपियां प्रदेश के मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव को सीधे भिजवाई हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सरकार इस तरह के सोशल ऑडिट को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए एक मजबूत और प्रभावी नीति तैयार करे।

बिना नाम, एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल के अब नहीं चलेगी कोर्ट स्लिप

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कोर्ट स्लिप के जरिए मामलों की लिस्टिंग कराने की अपारदर्शी व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अब प्रत्येक कोर्ट स्लिप पर संबंधित अधिवक्ता का पूरा नाम, एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सभी अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए

जाएंगे और सूचना काज लिस्ट में भी प्रकाशित की जाएगी।

दरअसल, जस्टिस विशाल धगत की सिंगल बेंच के समक्ष भैयाजी ठाकुर व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कुछ अधिवक्ताओं ने हस्तक्षेप आवेदन स्वीकृत हुए बिना ही वकालतनामा दाखिल कर रखा है। इसके बावजूद वे कोर्ट

स्लिप के माध्यम से लगातार प्रकरण की लिस्टिंग का आग्रह कर रहे थे। न्यायालय ने रिकार्ड का परीक्षण किया तो पाया कि प्रस्तुत कोर्ट स्लिप पर केवल हस्ताक्षर थे, लेकिन अधिवक्ता का नाम, एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज नहीं था। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए रजिस्ट्रार को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए।

इसी मामले में राज्य शासन और निजी पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में चार सप्ताह का समय दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद जवाब दाखिल करने का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगली सुनवाई 10 अगस्त 2026 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में होगी। तब तक अंतरिम राहत प्रभावी रहेगी।

वरिष्ठ अधिकारी बनकर मेजा फर्जी यूपीआई नंबर

व्हाट्सएप हैक कर 48 हजार की टगी

जबलपुर। साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाते हुए घंसीर एनटीपीसी पावर प्लांट में पदस्थ एक मैनेजर को अपना शिकार बना लिया। जालसाजों ने उनके वरिष्ठ अधिकारी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर उसी नंबर से मैसेज और कॉल कर 48 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। मामले की शिकायत मिलने के बाद गोराबाजार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार एनटीपीसी घंसीर पावर प्लांट में मैनेजर पद पर कार्यरत अमित राज गौतम ने 9 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 8 जुलाई की दोपहर करीब 1:30 बजे उनके वरिष्ठ अधिकारी अभय कुमार साहू के व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को अभय कुमार साहू बताते हुए तत्काल आर्थिक जरूरत बताई और 48 हजार रुपए भेजने के लिए एक यूपीआई नंबर साझा किया।

अधिकारी का व्हाट्सएप पहले ही हो चुका था हैक

अभय कुमार साहू ने बताया कि उनका व्हाट्सएप नंबर सुबह करीब 11 बजे ही हैक हो चुका था। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी दी थी। इसी हैक किए गए व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल कर साइबर ठगों ने मैनेजर को झंसे में लिया और रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली।

राजस्व अधिकारियों को मिले सब-रजिस्ट्रार के अधिकार

जबलपुर। मध्य प्रदेश में आबादी भूमि की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के तहत अब तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी सब रजिस्ट्रार के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2 जून को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बाद पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने इसका आधिकारिक

नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई व्यवस्था से प्रदेश के 48 लाख से अधिक परिवारों को आबादी भूमि पर मालिकाना हक मिलने का रास्ता आसान होगा। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत स्टॉप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और पंचायत उपकर पूरी तरह माफ कर दिया है। इन रियायतों का लाभभग 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी, जिससे पात्र हितग्राहियों को बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के रजिस्ट्री की सुविधा मिल सकेगी।

अब तहसील कार्यालय में होगी जमीनों की रजिस्ट्री

ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब रजिस्ट्री के लिए उप पंजीयक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिकृत राजस्व अधिकारी अपने-अपने तहसील कार्यालयों में ही स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी भूमि की रजिस्ट्री कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पंजीयन प्रक्रिया में तेजी आएगी, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा होगा और नागरिकों को समय पर वैध दस्तावेज उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश में कार्यरत 235 सब रजिस्ट्रार के साथ अब राजस्व अधिकारी भी इस व्यवस्था का संचालन करेंगे।

डिजिटल प्रक्रिया से बढ़ेगी पारदर्शिता

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के निर्देश जारी होने के बाद प्रदेशभर में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जरूरत पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर भी रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बुजुर्ग और दूरदराज के लोग आसानी से लाभ ले सकें। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं की संभावना कम होगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सभी पात्र परिवारों को उनकी आबादी भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं।